RNI : PBHIN/25/A4135

साप्ताहिक

सत्ता संदेश

सम्पादक : जितेंद्र कुमार
Website : www.sattasandesh.com
YouTube : @sattasandesh25
The Power of Print...

अभिनेत्री उर्मिला मतोंडकर ने किया 6

वर्ष : 2 अंक : 7 16 फरवरी : 2026 मूल्य रु. 5.00 /- पृष्ठ : 8 Email : sattasandesh25@ gmail.com

विक्टोरिया म्बोको ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन...8

आज का इतिहास

16 फरवरी 1923- ब्रिटिश संरक्षण से मुक्त हुआ मिस्र

16 फरवरी 1923 में मिस्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आया, जब ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से वहां से अपना संरक्षण समाप्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिस्र में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज़ हो गए थे और जनता ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति की मांग कर रही थी। लंबे संघर्ष और दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मिस्र को स्वतंत्रता मिली। हालांकि स्वतंत्रता के बावजूद ब्रिटेन का सैन्य और राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, फिर भी यह कदम मिस्र के लिए स्वशासन, संविधान निर्माण और आधुनिक राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत साबित हुआ। 1923 में ही मिस्र का नया संविधान लागू किया गया, जिसने देश में संवैधानिक शासन की नींव रखी और अरब राष्ट्रवाद को नई दिशा दी।

ट्रंप की ईरान को चेतावनी

परमाणु समझौता करो, वरना बेहद भयावह होंगे परिणाम

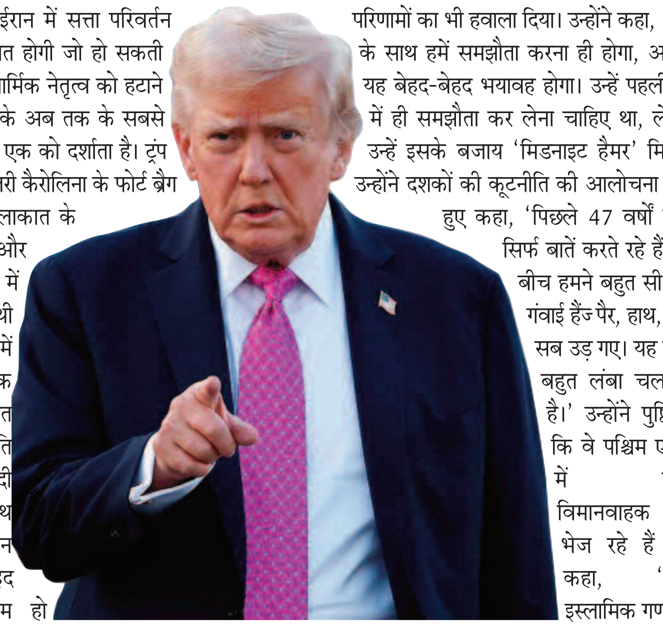

वाशिंगटन- अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन 'सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है'। जो देश के धार्मिक नेतृत्व को हटाने के समर्थन में उनके अब तक के सबसे स्पष्ट बयानों में से एक को दर्शाता है। ट्रंप ने ये टिप्पणियां उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के तुरंत बाद की और इससे पहले दिन में उन्होंने पुष्टि की थी कि वह मध्य पूर्व में दूसरा विमानवाहक पोत समूह तैनात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ परमाणु समझौता न होने पर 'बेहद भयावह' परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने अतीत के सैन्य हमलों और संभावित परिणामों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'ईरान के साथ हमें समझौता करना ही होगा, अन्यथा यह बेहद-बेहद भयावह होगा। उन्हें पहली बार में ही समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्हें इसके बजाय 'मिडनाइट हैमर' मिला।' उन्होंने दशकों की कूटनीति की आलोचना करते हुए कहा, 'पिछले 47 वर्षों से वे सिर्फ बातें करते रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सी जानें गंवाई हैंज पैर, हाथ, चेहरे सब उड़ गए। यह संघर्ष बहुत लंबा चल रहा है।' उन्होंने पुष्टि की कि वे पश्चिम एशिया में दूसरा विमानवाहक पोत भेज रहे हैं और कहा, 'अगर इस्लामिक गणराज्य के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होता।' जब उनसे पूछा गया कि ईरान का नेतृत्व कौन संभालेगा, तो उन्होंने कहा, 'कुछ लोग हैं' लेकिन कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अभी तक राष्ट्रपति ट्रम्प की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी मुलाकात के बाद कोई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, मुलाकात का एकमात्र रिकॉर्ड ओवल ऑफिस में हाथ मिलाना था, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वितरित किया गया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप के बयान में निरंतर वार्ता की उनकी इच्छा पर जोर दिया गया, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के परमाणु समझौते के विरोध और ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर चर्चा करने में उनकी कथित रुचि के विपरीत था।

अमेरिका का बड़ा एक्शन

सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

अमेरिकी सेना ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर सिलसिलेवार तरीके से कई हवाई हमले किए जाने की जानकारी शनिवार को दी। ये हमले दिसंबर में हुए उस हमले के जवाब में किए गए थे जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक अनुवादक मारा गया था।

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी विमानों ने तीन फरवरी से बृहस्पतिवार के बीच आईएस के 30 से अधिक ठिकानों पर 10 हमले किए, जिनमें हथियार भंडारण सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।

केंद्रीय कमान के अनुसार, 13 दिसंबर के हमले के बाद अमेरिका द्वारा हमले शुरू किए जाने के बाद से आईएस के कम से कम 50 सदस्य मारे गए या पकड़े गए, जबकि आईएस के 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं। उस हमले में सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड और नागरिक अनुवादक अयाद मंसूर सकात मारे गए थे।

आप विधायक कुलवंत सिद्धू को मिली धमकी

लुधियाना (सत्ता संदेश)- लुधियाना के आत्म नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक को विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। इसके साथ ही देर रात उनके घर के बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां भी देखी गईं। इस संबंध में विधायक की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जाह्नवी कंदूला मामले में नया सदमा, मुआवज़े के ऐलान से दो दिन पहले पिता का निधन

अडोनी- अमेरिका में पुलिस वाहन की टक्कर से मारी गई भारतीय छात्रा जाह्नवी कंदूला के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। जाह्नवी के पिता कंदूला श्रीकांत, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल थे, का 10 फरवरी को आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह दुखद घटना उस समय हुई, जब इसके ठीक दो दिन बाद अमेरिकी अदालत द्वारा परिवार को 29 मिलियन डॉलर (लगभग 260 करोड़ रुपये) मुआवज़ा दिए जाने का ऐलान किया गया। जाह्नवी की उम्र 23 वर्ष थी और वह नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल कैंपस में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थीं। 23 जनवरी 2023 को सड़क पार करते समय एक तेज़ रफ्तार पुलिस वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी।

प्रधानमंत्री को लेकर हाईवे पर उतरा वायुसेना का वॉरबली

सीमा पर चीन की हर चाल को नाकाम करेगा भारत

नई दिल्ली(सत्ता संदेश)-मुख्य तौर से भारत-चीन सीमा को सुरक्षित रखने में रणनीतिक तौर पर बड़ी ताकत देने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ में वायुसेना के हरक्यूलिस सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारत-चीन सीमा से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सुविधा चीन की किसी भी आपात स्थिति में भी प्रभावी साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के वॉरबली विमान सी-130जे सुपर हरक्यूलिस से असम के डिब्रूगढ़ में उतरकर भारत की मजबूत सैन्य क्षमता और तैयारियों का स्पष्ट संदेश दिया। असम में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर तैयार इस हाईवे एयरस्ट्रिप पर 127 फीट चौड़ाई और 4.2 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार किया गया है, जिससे युद्धक विमानों की आवाजाही संभव हो सकेगी। डिब्रूगढ़ में सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान उन्होंने रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया।

राफेल, सुखोई ने दिखाई ताकत

उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने हाईवे से टेकऑफ और लैंडिंग कर यह दिखाया कि किसी भी आपात स्थिति में देश की वायुसेना पूरी तरह सक्षम और तैयार है।

बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी- रहमान

ढाका(सत्ता संदेश)-- बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सुरक्षित और मानवता का सम्मान करने वाला देश बनाने में सहयोग करने की अपील की। रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने शुक्रवार को ऐतिहासिक संसदीय चुनावों में दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की। रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वह अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस की जगह लेंगे। रहमान ने 13वें संसदीय चुनावों में भारी जीत के एक दिन बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सुरक्षित और मानवता का सम्मान करने वाला बांग्लादेश बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

इस बार देश के पुनर्निर्माण में सभी को जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी बहाने किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी। देश के स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों ने बीएनपी को विजयी बनाया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को जनता की जीत बताया। देश के निर्माण में सभी के विचार महत्वपूर्ण बीएनपी अध्यक्ष ने कहा कि आज से सभी स्वतंत्र हैं। आप सभी को बधाई। सभी की भागीदारी के साथ देश में फासीवाद-मुक्त सरकार की यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में सभी के विचार महत्वपूर्ण हैं। हम सभी की राय के आधार पर देश का निर्माण करेंगे। निर्वाचन आयोग (ईसी) के अनुसार, बीएनपी ने 297 में से 209 सीट जीतीं, जबकि दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी को 68 सीट पर जीत मिलीं। हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

प्रो. भुल्लर मामले की अदालत में सुनवाई टली, अब 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली(सत्ता संदेश)- हाल ही में दविंदर पाल सिंह भुल्लर की दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा एक बार फिर समय से पहले रिहाई से इनकार किए जाने के बाद पंथ में गहरी निराशा फैल गई थी। इसके बाद अदालत में चल रहे इसी मामले में बीते दिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई।

पंथक वकील भाई जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि अदालत में मामलों की अधिक संख्या होने के कारण प्रो. भुल्लर जी के केस का नंबर नहीं आ सका, जिसके चलते अदालत ने सुनवाई के लिए 25 फरवरी की अगली तारीख तय कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले डेढ़ दशक से प्रो. भुल्लर सिज़ोफ्रेनिया (मानसिक विकार) से पीड़ित हैं और अमृतसर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।

पहले केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार और दिल्ली में 'आप' सरकार इस मामले पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती रही थीं। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जत्थेदार अकाल तख्त साहिब से मुलाकात के बाद सकारात्मक नतीजे की उम्मीद थी, क्योंकि भाजपा केंद्र और दिल्ली– दोनों में सत्ता में है। बावजूद इसके, सिखों को दूसरे दर्जे का नागरिक होने का एहसास करवा दिया गया, जिससे उम्मीदें टूट गईं।

डेरा ब्यास का बड़ा फैसला- अब वीआईपीज के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों

अमृतसर (सत्ता संदेश)- राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से एक अहम और दूरगामी फैसला लिया गया है। यह निर्णय डेरा परिसर में वीआईपी ट्रीटमेंट और प्रचार से जुड़ा हुआ है। नए निर्देशों के अनुसार अब डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ किसी भी वीआईपी हस्ती की तस्वीरें न तो खिंचवाई जाएंगी और न ही सार्वजनिक रूप से जारी की जाएंगी।

मिली जानकारी के अनुसार बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों अब किसी भी वीआईपी के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे। इसके साथ ही डेरा ब्यास में अब किसी भी प्रकार का विशेष वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में डेरा प्रबंधन की ओर से एक सर्कुलर जारी कर फोटो खींचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। डेरा प्रबंधन का कहना है कि यह कदम डेरा की आध्यात्मिक परंपरा, मर्यादा और सादगी को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रबंधकों के अनुसार सत्संग का मूल उद्देश्य आत्मिक उन्नति, सिमरन और साधना होना चाहिए, न कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवाना या किसी प्रकार का प्रचार। डेरा प्रबंधक समिति ने संगत से अपील की है कि वे डेरा की मर्यादा और नियमों का पूरी तरह पालन करें और सत्संग के दौरान फोटोग्राफी से परहेज करें। डेरा का मानना है कि इस फैसले से सत्संग की पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक मजबूत होगा।

विदेश में बैठे गैंगस्टर ने दी पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी को धमकी, 10 करोड़ की मांगी फिरौती

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)- पंजाबी अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने मोहाली पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में दावा किया है कि उन्हें विदेश में रहने वाले एक गैंगस्टर ने धमकी देते हुए 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। मोहाली पुलिस ने कहा कि अभिनेत्री से मिली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि खुराना ने अपनी ईमेल आईडी पर प्राप्त जबरन वसूली के ईमेल के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शनिवार को सोहाना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4) (जबरन वसूली) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक (जांच) सौरभ जिंदल ने कहा, 'शिकायत के अनुसार, ईमेल के साथ एक 'ऑडियो' संलग्न किया गया था जो कथित तौर पर विदेश में रहने वाले एक गैंगस्टर द्वारा भेजा गया था। इसमें 10 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी।'

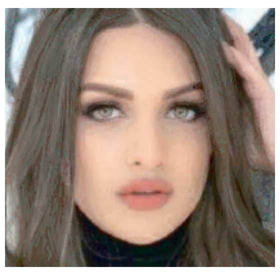

दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश, चीनी दावा निकला 'फेक'

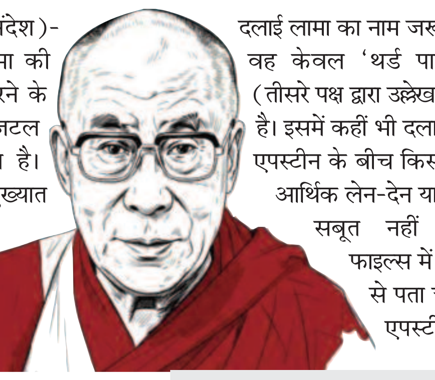

धर्मशाला (सत्ता संदेश)- तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की वैश्विक छवि को धूमिल करने के लिए चीन ने अब 'डिजिटल प्रोपेगैंडा' का सहारा लिया है। चीनी सरकारी मीडिया ने कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एपस्टीन की फाइल्स का दुरुपयोग करतें हुए दलाई लामा का नाम उससे जोडने की कोशिश की है। हालांकि, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने वैज्ञानिक जांच और पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी 'एपस्टीन फाइल्स' के करीब 35 लाख पन्नों की केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की संकट प्रबंधन समिति और तिब्बती कंप्यूटर रिसोर्स सेंटर ने गहन तकनीकी जांच की। विश्लेषण में सामने आया कि फाइल्स में दलाई लामा का नाम जरूर है, लेकिन वह केवल 'थर्ड पार्टी रेफरेंस' (तीसरे पक्ष द्वारा उल्लेख) के तौर पर है। इसमें कहीं भी दलाई लामा और एपस्टीन के बीच किसी मुलाकात, आर्थिक लेन-देन या पत्राचार का सबूत नहीं मिला है। फाइल्स में मौजूद ईमेल से पता चलता है कि एपस्टीन और उसके सहयोगी 2012 से 2017 के बीच दलाई लामा से मिलने की बेताब कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी अनुमति नहीं मिली। विश्लेषण के अनुसार दलाई लामा नाम का उल्लेख केवल अनौपचारिक और अनुमानित संदर्भों में हुआ है। यह किसी मुलाकात की पुष्टि नहीं करता । दलाई लामा की वेबसाइट पर 1959 से लेकर अब तक की हर. छोटी-बड़ी मुलाकात का रिकॉर्ड सार्वजनिक है। इसमें एपस्टीन का कहीं कोई जिक्र नहीं है

दलाई लामा ने जापान की प्रधानमंत्री को दी बधाई

जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सना ताका इची को तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु परम पावन-14वें दलाई लामा ने पत्र लिखकर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दलाई लामा ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जापान की जनता ने उनके सक्षम नेतृत्व पर भरोसा जताया है। दलाई लामा ने अपने संदेश में लिखा कि आज की दुनिया कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे समय में दया, करुणा और दूसरों के कल्याण के लिए ईमानदार चिंता पर आधारित नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने स्वतंत्र मीडिया और जनता से की अपील

विवाद बढ़ता देख दलाई लामा के कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि परम पावन ने कभी जेफरी एपस्टीन से मुलाकात नहीं की है और न ही अपनी ओर से किसी को उनसे बात करने के लिए अधिकृत किया है। ये आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत हैं। चीनी मीडिया के इस भ्रामक अभियान के जाल में कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस भी फंस गए। भारतीय अंग्रेजी अखबार 'द फाइनेंशियल एक्सप्रेस' ने एक लेख छापा था, जिस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक सचिव ताशी ग्यात्सो ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2015 के ईमेल खुद इस बात का सबूत हैं कि 2012 में कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि एपस्टीन 2015 में भी मुलाकात के लिए हाथ-पांव मार रहा था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने स्वतंत्र मीडिया और जनता से अपील की है कि वे चीनी दुष्प्रचार का हथियार न बनें और किसी भी सनसनीखेज दावे को सांझा करने से पहले तथ्यों की पड़ताल जरूर करें।

बुजुर्गों की सुरक्षा व अधिकारों पर पहरेदारी जमीनी हकीकत से कोसों दूर

मैट्रो शहरों में बुजुर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधिक मामलों में इंसाफ प्रक्रिया बेहद सुस्त

बठिंडा (सत्ता संदेश)-देशभर में बुजुर्गों के लिए इंसाफ लेना और कठिन हो गया है। बुजुर्गों के लिए सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं, बल्कि उनके केसों का निपटारा और पुलिस की संवेदनशीलता की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी दावे चाहे कुछ भी हों परंतु बुजुर्गों की सुरक्षा व उनके अधिकारों पर पहरेदारी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। केन्द्र सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर राज्य सरकारों पर डालकर अपने आपको अलग कर लिया है। नैशनल क्रइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने भारत के बड़े शहरों में रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा संबंधी एक भयानक तस्वीर पेश की है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली बुजुर्गों के विरुद्ध अपराधों के मामले में शिखर पर है, जहां वर्ष 2023 में 1,361 मामले दर्ज किए गए। इसके उलट, पूर्वी भारत का महानगर कोलकाता बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित साबित हुआ है, जहां पूरे वर्ष मात्र 6 केस ही दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मैट्रो शहरों में बुजुर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में इंसाफ की प्रक्रिया बेहद सुस्त है। वर्ष 2023 के अंत तक, 19 प्रमुख शहरों में कुल 13,483 केस अदालती सुनवाई अधीन थे। मुंबई में 2,755 केस और अहमदाबाद में 2,675 केस लम्बित हैं। चिंता की बात यह है कि अहमदाबाद जैसे शहर में 2021 से 2023 के बीच सज़ा की दर लगातार शून्य रही है। हालांकि दिल्ली ने इस दिशा में सुधार दिखाया है, जहां सज़ा की दर 2021 में 11.4 फीसदी थी, जो 2023 में बढ़कर 48.7 फीसदी हो गई। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस व पब्लिक ऑर्डर राज्य के विषय हैं, इसलिए बुजुर्गों की जान-माल की सुरक्षा राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर प्रदेश में कई ऐसे आई.पी.एस. व आईएस अधिकारी हैं जोकि बुजुर्गों की बात तक सुनने को प्राथमिकता नहीं देते और मामले का हल करना तो दूर की बात है। हालांकि 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के समय के लिए 1,800 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की सिफारिश की थी, परंतु आकड़े बताते हैं कि 31 अक्तूबर 2025 तक देशभर में सिर्फ 866 फास्ट ट्रैक अदालतें ही कार्यशील है। केन्द्र सरकार ने बार-बार राज्यों को इन अदालतों के लिए फंड जारी करने की अपील की है परंतु ज़मीनी स्तर पर लक्षय अभी काफी दूर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुजुर्गों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हैल्पलाइन 'एल्डरलाइन' (14567) चलाने के दावे किए जा रहे हैं। यह भी कि हैल्पलाइन बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं बारे जानकारी देने और उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करती है परंतु हैरानी की बात यह है कि यह महत्वपूर्ण सेवा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में अभी तक शुरू नहीं हो सकी। यहां ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि पंजाब में बुजुर्गोंकी आबादी भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रही है। 2024 2026 के अनुमानों के अनुसार पंजाब में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या लगभग 40 लाख के करीब है जोकि देश की औस्त लगभग 10 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। यह भी पता चला है कि पंजाब की विभिन्न जिला अदालतों व हाईकोर्ट में बुजुर्गों से संबंधित लगभग हज़ारों मामले ज़मीनी विवाद, गुजारा भत्ता व घरेलू हिंसा शामिल हैं, विचाराधीन हैं, हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिए हैं कि बुजुर्गों से संबंधित केसों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों की भलाई के लिए 2025-26 के बजट में 786.83 लाख रुपए रखे गए हैं, और प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक सरकारी वृद्ध आश्रम बनाने का ऐलान किया गया है परंतु इसके बावजूद सरकार को चाहिए कि वह अपने सीनियर सिटीजन का ख्याल रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी व अन्य विभागों के उचित निर्देश जारी करे।

सोशल मीडिया पर गलत सामग्री व अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कारवाई

साइबर सैल की रहेगी सोशल मीडिया पर तीखी नजर, शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जायेगा

पटियाला (सत्ता संदेश)- आधुनिकता के इस युग में अपने निजी काम और रोजगार के चक्कर में 'यादातर व्यक्ति मोबाइल व कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु इनका दुरुपयोग करने वालों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ए.आई. के युग में शरारती तत्व किसी व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने के लिए उसकी फर्जी तस्वीर बनाकर अश्लील सामग्री जोड़कर वायरल करके उस व्यक्ति की छवि खराब कर देते हैं। ऐसा फिल्मी कलाकारों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ कई बार हो चुका है। इस संबंधी पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। माननीय अदालत ने भी ऐसे मामलों संबंधी कई निर्देश जारी किए हैं, जिसके मद्देनजर पंजाब पुलिस द्वारा इस मामले में भी साइबर थानों में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी ताजा उदाहरण पटियाला के साइबर सैल में किसी व्यक्ति द्वारा एक बच्चे की गलत वीडियो सोशल मीडिया पर सांझा करने के मामले में पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विशेष रूप से लड़कियों की फोटो से छेड़छाड़ करके उनकी छवि खराब करने वाले व्यक्तियों पर भी साइबर सैल की तीखी नजर है। पंजाब पुलिस का यह विभाग सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निरंतर नजर रख रहा है। ऐसी कार्रवाई करने वाले कई शरारती तत्वों के सोशल मीडिया के खाते भी बंद करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में एस.एस.पी. वरुण शर्मा ने बताया कि पटियाला साइबर सैल की टीम सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के साथ शरारती तत्वों को काबू करने में विशेष भूमिका निभा रही है।

सरकार बनने पर कबड्डी कप फिर शुरू करेंगे- सुखबीर बादल

'आप' के दिल्ली नेताओं पर पंजाब को लूटने और कुचलने के आरोप

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)- शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने पर विश्व कबड्डी कप दोबारा शुरू कराया जाएगा। वह आज देर शाम नज़दीकी गांव बल्लोमाजरा में सुखविंदर सिंह छिंदी और उनके साथियों द्वारा आयोजित कबड्डी कप के अवसर पर खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली सरकार के कार्यकाल के दौरान लड़कों और लड़कियों के लिए कबड्डी के विश्व कप आयोजित किए गए थे। इससे न केवल करोड़ों रुपये के इनाम दिए गए, बल्कि कबड्डी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान भी मिला। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी दी गई थीं। उन्होंने कहा कि अकाली सरकार जाने के बाद पिछले दस वर्षों में किसी भी सरकार ने कबड्डी की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब में अकाली सरकार बनने पर जहां कबड्डी के विश्व कप दोबारा शुरू किए जाएंगे, वहीं साथ ही मारवाड़ी घोड़ों और कुत्तों की दौड़ों के भी करोड़ों रुपये इनाम वाले मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार के समय मोहाली क्षेत्र का व्यापक विकास हुआ था। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली से आए नेता जनता की सेवा करने के बजाय पंजाब को लूटने और लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है।

हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में पानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का गंभीर खतरा

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)- हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पानी अब केवल बुनियादी सुविधा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का गंभीर खतरा बन गया है। इंटीग्रेटेड हैल्थ डाटा के ताजा विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 5 वर्षों में इन राज्यों में जलजनित बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ इसे 'साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी' कह रहे हैं। पंजाब में पिछले पांच सालों में 38,000 से अधिक एक्यूट डायरियल डिजीज (एडीडी) के मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा में टायफाइड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर तेजी से शहरीकरण वाले जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक में। हिमाचल प्रदेश में एडीडी के साथ-साथ हेपेटाइटिस-बी के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जो यह संकेत देता है कि पहाड़ी जलस्रोत अब सुरक्षित नहीं रहे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ मौसमी उछाल नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली की संरचनात्मक खामियों का नतीजा है। पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों में दशकों पुरानी पाइपलाइनें अभी भी इस्तेमाल में हैं। कई जगह पाइपलाइनें सीवेज नेटवर्क के बहुत करीब बिछी हुई हैं। जर्जर पाइपों में मामूली लीकेज भी दूषित पानी को सीधे सप्लाई में मिला देता है। गर्मी और बरसात के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, और इस दौरान एडीडी के मामलों में अचानक उछाल देखने को मिलता है। रिपोर्टों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इन तीनों राज्यों में एडीडी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और अन्य जलजनित रोगों के हजारों मामले दर्ज किए गए। पंजाब में 38,000 से अधिक एक्यूट डायरियल डिजीज यानी एडीडी के मामले सामने आए। हरियाणा में टाइफाइड के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, खासकर तेजी से विकसित होते शहरी जिलों में। हिमाचल प्रदेश में मानसून के बाद दस्त और हेपेटाइटिस से जुड़े मामलों में उछाल देखा गया। नेशनल सेंटर फार डिसिजिज कंट्रोल की रोग निगरानी प्रणाली बताती है कि जलजनित रोगों में मौसमी बढ़ोतरी सामान्य है, लेकिन लगातार ऊंचे बने रहना आपूर्ति और गुणवत्ता नियंत्रण की कमजोरी की ओर इशारा करता है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पानी की गुणवत्ता को लेकर उठते सवाल केवल आंकड़ों की कहानी नहीं हैं। यह घर घर तक पहुंचने वाली व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न है। पानी दिखने में साफ हो सकता है, लेकिन रिपोर्टों में सामने आए तथ्य संकेत देते हैं कि सतर्कता और सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

इंटीग्रेटेड हैल्थ डाटा के ताजा विश्लेषण से पता चला

क्या कहती है रिपोर्ट

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में पंजाब के कई जिलों में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई। मीडिया रिपोर्टों में लगभग 62.5 प्रतिशत नमूनों में मानक से अधिक स्तर का उल्लेख किया गया। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे तत्व भी कई क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज किए गए। इसका अर्थ है कि समस्या केवल बैक्टीरिया से फैलने वाले संक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर मौजूद है। जमीनी रिपोर्टों में सामने आया कि कई शहरों और गांवों में दशकों पुरानी पाइपलाइनें आज भी उपयोग में हैं। पेयजल और सीवेज लाइनें कई स्थानों पर बेहद नजदीक बिछी हैं। जंग लगे पाइपों में मामूली लीकेज भी दूषित पानी को सीधे सप्लाई में मिला देता है। हरियाणा के शहरी विस्तार वाले क्षेत्रों में नई कॉलोनियों का दबाव पुरानी व्यवस्था झेल नहीं पा रही। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइन रखरखाव की कमी सामने आई। मानसून और गर्मी के महीनों में संक्रमण के मामलों में उछाल इसी संरचनात्मक कमजोरी की ओर संकेत करता है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोतों को पारंपरिक रूप से सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन भारी वर्षा, भूस्खलन और मिट्टी के बहाव से स्रोत दूषित हो रहे हैं। कई गांवों में मानसून के दौरान पानी के रंग और गंध में बदलाव की शिकायतें दर्ज की गईं। वर्ल्ड बैंक की ग्रामीण पेयजल प्रबंधन पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट में स्रोत संरक्षण, नियमित सैंपलिंग और सामुदायिक निगरानी की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में भी वैज्ञानिक निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

योजनाएं और जमीनी हकीकत

जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कनेक्शन देना पर्याप्त नहीं है। नियमित क्लोरीनीकरण-पाइपलाइन का समय पर रख-रखाव, मासिक जल गुणवत्ता रिपोर्ट का प्रकाशन, स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण जैसे कदमों के बिना भरोसा कायम नहीं रह सकता। कुछ शहरों में राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने की पहल की गई है, लेकिन व्यापक स्तर पर निगरानी अभी भी चुनौती है।

विशेषज्ञों की चेतावनी

जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते संरचनात्मक सुधार नहीं किए गए तो जलजनित रोगों का बोझ बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वे सुझाव देते हैं कि जर्जर पाइपलाइन का चरणबद्ध पुनर्निर्माण किया जायेए ,सीवेज और पेयजल लाइनों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित किया जाये, मानसून से पहले जल स्रोतों का वैज्ञानिक ऑडिट और जल गुणवत्ता डेटा को सार्वजनिक किया जाये।

पंजाबी गायक परमीश वर्मा की प्रशंसकों से झड़प, लाइव शो के दौरान हुई बहस

नई दिल्ली(सत्ता संदेश)- मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता परमीश वर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली में एक लाइव शो के दौरान उनकी एक प्रशंसक से तीखी झड़प हो गई। घटना के दौरान परमीश वर्मा ने अचानक गाना रोक दिया और स्टेज से प्रशंसक की ओर थप्पड़ दिखाते नजर आए। बहस बढ़ने पर मौके पर मौजूद पुलिस और परमीश वर्मा के निजी सुरक्षा गार्डों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में परमीश वर्मा प्रशंसक से बहस करते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वीडियो में उनकी आवाज़ साफ़ नहीं सुनाई देती। वर्मा और प्रशंसक के बीच बातचीत एक मिनट से अधिक समय तक चली। जानकारी के अनुसार, गायक परमीश वर्मा 13 फरवरी की शाम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 'दिल्ली खेल महाकुंभ' के उद्घाटन समारोह के दौरान लाइव प्रस्तुति दे रहे थे। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू हुआ था। प्रवेश निःशुल्क था, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य रखा गया था। फिलहाल, इस मामले पर परमीश वर्मा या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सिद्धू मूसेवाला के पिता की पोस्ट- जो सिद्धू के साथ थे, आज ढूंढने पर नहीं मिल रहे

मानसा (सत्ता संदेश)- मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला संगीत के शिखर पर थे तो अनेकों लोग व साथी उनके साथ थे और उससे अपना नाम जोड़ रखा था। ऐसे लोग आज ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग निजी जरूरत को अपना हक समझते रहे तथा उनके नाम से अपनी पहचान जोड़ते रहे, लेकिन आज वह इंसाफ लेने के समय चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ये सच है कि हम जिसे दुख व हादसे में गंवा देते हैं, उसके बाद ही लोगों की असलियत सामने आती है। मुश्किल वक्त में बदले हुए लोग बेशक, जितने चाहे अच्छे हों, लेकिन दिल उतर जाते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मानसा एसएसपी दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ, उसकी कोई योजना नहीं थी, वह सबकुछ अचानक हुआ। कुछ लोगों ने वहां तथा विदेश से भी उनका सहयोग कर रहे हैं, जो आज भी उनके साथ खड़े हैं, ऐसे लोगों पर उन्हें गर्व है, जिनकी हिम्मत व सहयोग से वह अपने पुत्र के लिए इंसाफ लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों के हमेशा आभारी रहेंगे, जिन्होंने आज तक भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। बलकौर सिंह सिद्धू ने कहा कि वह इंसाफ लेकर रहेंगे और सिद्धू मूसेवाला की अमानत को कभी भी मिटने नहीं देंगे।

27 से शुरू हो रहे होला महल्ला की पूर्व तैयारियों व प्रबंधन को लेकर शिक्षा मंत्री ने की समीक्षा बैठक

श्रद्धालुओं की आसान यात्रा के लिए मुफ्त 60 शटल बस और 100 ई-रिक्शा सेवा

श्री आनंदपुर साहिब/चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-श्री आनंदपुर साहिब में 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाले होला महल्ला पर्व के मद्देनजर शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने रूपनगर जिले के अधिकारियों के साथ तैयारियों और प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को संगत की सुविधा के लिए 8 एकड़ में टैंट सिटी, ट्रॉली सिटी और 25 पार्किंग जोन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आसान यात्रा के लिए मुफ्त 60 शटल बस और 100 ई-रिक्शा सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। बैंस ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने वाली संगत के लिए यातायात यकीनी बनाने और शहर को साफ-सुथरा रखा जाए। विरासत-ए-खालसा में आतिशबाजी होगी और पूरी गुरुनगरी को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। बैंस ने राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों को लेकर मीटिंग में अफसरों को बताया कि प्रबंधों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि कई श्रद्धालु अपनी सजी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में ही ठहरते हैं, जिसके लिए व्यवस्था की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्किंग स्थलों पर हैल्प डैस्क, पेयजल, लाइट, शौचालय, ई-रिक्शा और शटल बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रद्धालुओं को मेले की जानकारी देने के लिए 20 एल.ई.डी. स्क्रीन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब में स्वच्छता, पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, यातायात, सुरक्षा और सेहत सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए जाएं। मेला क्षेत्र को 11 सैक्टरों में विभाजित किया जाए और हर सैक्टर में आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, वहां डॉक्टरों की टीमें मुफ्त सेहत सेवाएं प्रदान करेंगी। सुरक्षा के तहत विशेष टीमें गठित की गई हैं और हर सेक्टर में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब की सीमा में शराब, मांस, तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। डी.सी. आदित्य डेचलवाल ने कीरतपुर साहिब में 27 फरवरी से 1 मार्च और श्री आनंदपुर साहिब में 2 मार्च से 4 मार्च तक 3 किमी के दायरे में आने वाले सभी प्रकार के शराब ठेके, अहाते, भंडारण स्थल और होटल में शराब की बिक्री-प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। मीटिंग में एस.एस.पी. मनिंदर सिंह आदि अफसर मौजूद थे।

केंद्र की 'पीएम-आशा' योजना पंजाब में नहीं होगी लागू

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)- पंजाब सरकार ने किसानों को फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने वालीं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम- आशा) को अपनाने से इन्कार कर दिया है। राज्य संरकार का कहना है कि इस योजना से जुड़ी शर्तें पंजाब की मौजूदा कृषि व्यवस्था, खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मंडी प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं। यह फैसला पिछले दिनों हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग के चेयरमैन सुखपाल सिंह और कृषि निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, पीएम-आशा के तहत लागू की जाने वाली प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस.) और प्राइस स्टेबिलाइजेशन स्कीम (पी.एस.एस.) को अपनाने के लिए राज्यों को माडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टाक मार्केटिंग एक्ट, 2017 को स्वीकार करना अनिवार्य है, जिसे पंजाब पहले ही खारिज कर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यह 2017 का कानून निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है और पारंपरिक मंडी व्यवस्था से बाहर व्यापार को आसान बनाता है। पंजाब सरकार को आशंका है कि इससे कृषि क्षेत्र में निजीकरण बढ़ेगा, एमएसपी आधारित सरकारी खरीद कमजोर होगी और राज्य को कर एवं शुल्क में भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। यही नहीं, इससे न केवल किसानों, बल्कि हजारों आढ़तियों की आजीविका पर भी असर डालेगा।

वडाला ने दी शिरोमणि कमेटी चुनावों में देरी के खिलाफ मोर्चा लगाने की चेतावनी

शिरोमणि अकाली दल पुनर्सरजीत द्वारा जालन्धर में कान्फ्रैंस 19 फरवरी को

जालन्धर (सत्ता संदेश)- शिरोमणि अकाली दल पुनर्भुरजीत के सचिव जनरल जत्थेदार गुरप्रताप सिंह वडाला ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में लगातार हो रही देरी के खिलाफ मोर्चा लगाने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शिरोमणि कमेटी के चुनाव शीघ्र न करवाए गए तो पार्टी संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने आज यहां एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले लम्बे समय से शिरोमणि कमेटी के चुनाव न होने के कारण सिख जगत में भारी रोष पाया जा रहा है। इस मौके उन्होंने 328 सरूपों के मामले में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा पुलिस प्रमुख के साथ की गई मुलाकात को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि सिख भावनाओं के साथ जुड़े मसले पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस मसले पर शिरोमणि कमेटी द्वारा समय पर कार्रवाई की जाती तो आज अदालतों को इस मामले में दखल देने की जरूरत न पड़ती। इस मौके जत्थेदार वडाला ने प्रो. दविंदरपाल सिंह भुल्लर के मामले में भी केन्द्र की भाजपा सरकार के नकारात्मक व्यवहार की कड़ी अलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ डेरा सिरसा प्रमुख को वर्ष में अनेक बार पैरोल मिल रही है, जबकि सिख बंदियों के मामले में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। इस मौके राज्य की लगातार बिगड़ती जा रही अमन कानून की स्थिति और गैंगस्टरवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इस मौके उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब को दरपेश विभिन्न चुनौतियों पर विशेषकर सिख कौम के मसलों संबंधी पार्टी द्वारा एक विशाल कान्फ्रैंस 19 फरवरी दिन वीरवार को प्रतापपुरा दाना मंडी निकट लांबड़ा में करवाई जा रही है, जिसमें पार्टी प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह व अन्य वरिष्ठ लीडरशिप विशेष तौर पर शामिल होगी। इस अवसर पर उनके साथ स. अवतार सिंह कलेर, बीबी हरजीत कौर तलवंडी, जरनैल सिंह गढ़दीवाला, जालन्धर शहरी के प्रधान अमरजीत सिंह किशनपुरा, देहाती प्रधान सुखवंत सिंह रौली, महिंदरपाल सिंह बिनाका, जसविंदर सिंह डॉलफिन, जसविंदर सिंह जस्सा, सतनाम सिंह, केवल सिंह चंदी आदि भी उपस्थित थे।

पंजाब में 2 दिन बारिश की संभावना

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)- पंजाब में मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशभर में धूप खिली रहेगी और पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएं कमजोर पड़ने के कारण तापमान में गिरावट थम गई है। दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है, जिससे ठंड का असर अब धीरे-धीरे कम होता दिखाई दे रहा है।

16 फरवरी से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस- मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी 2026 की रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डाल सकता है। इसके प्रभाव से 17 और 18 फरवरी को पंजाब के कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बादल छाने के भी आसार हैं। फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और मोगा जिलों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि भारी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम में बदलाव से दिन और रात के तापमान पर असर पड़ेगा।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने ही खोल दी अपने मंत्रियों की पोल

कहा, नगर निगमों से संबंधित 1100 से ज्यादा प्रस्ताव लंबे समय से लोकल बॉडी विभाग में 2018 से लम्बित पड़े हैं

लुधियाना (सत्ता संदेश)-पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़े विवादों की लिस्ट दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है। इसमें ताजा मामला नए लोकल बॉडी मंत्री की प्रेस कान्फ्रैंस के बाद सामने आया है। यह प्रेस कान्फ्रैंस मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा नए लोकल बॉडी विभाग में पिछले कुछ दिनों के दौरान किए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य की विभिन्न नगर निगमों द्वारा पास करके भेजे गए 900 प्रस्तावों को 3 हफ्ते में क्लियर कर दिया गया है और आगे से कोई भी प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करके मंजूरी देने के लिए 10 दिन की डेडलाइन फिक्स की गई है। इसके साथ ही अरोड़ा ने यह कहकर पिछले मंत्रियों पर सवाल खड़े कर दिए कि विभिन्न नगर निगमों से संबंधित 1100 से ज्यादा

प्रस्ताव लंबे समय से लोकल बॉडी विभाग में 2018 से लम्बित पड़े हुए थे, जिससे लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जरूरी विकास कार्यों में देरी हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया में मैनुअल सिस्टम खत्म करके टाइम बाउंड पैटर्न के साथ ई निगम लागू कर दिया गया है। इन फैसलों को अरोड़ा द्वारा लोकल बॉडीज विभाग में गवर्नेंस रिफार्म का नाम दिया गया है कि अब मामलों की फास्ट क्लीयरेंस के लिए सेंट्रलाइज तरीके से फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद से चर्चा छिड गई है कि क्या इससे पहले 3 साल तक आप की सरकार के दौरान लोकल बॉडीज विभाग के मंत्रियों द्वारा इस तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए, जिन्हें अब अरोड़ा द्वारा मिशन मोड अर्बन डिवैल्पमैंट का नाम दिया गया है। अरोड़ा ने विकास कार्यों के लिए टैंडर लगाने या वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में हो रही देरी की पोल खोल कर रख दी है कि अब तक फाइल को कई अधिकारियों के पास भेजने में काफी समय लगता था, लेकिन अब हालात में सुधार लाने के लिए एक ही चीफ इंजीनियर को पूरे जिले की सभी ब्रांचों का चार्ज दे कर फाइल क्लियर करने के लिए 10 दिन की डेडलाइन फिक्स की गई है। इसके अलावा लोकल लेवल पर 2 करोड़ तक की लागत के विकास कार्यों को टैक्निकल मंजूरी देने का सिस्टम लागू किया गया है, जिसे लेकर अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे लोकल बॉडीज विभाग में अब तय समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से वित्तीय व प्रशासनिक फैसले बिना रुकावट के लागू होने का दावा अरोड़ा द्वारा किया गया है।

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 22 किलो से ज़्यादा हेरोइन, हथियार और ड्रग मनी के साथ 4 लोग गिरफ्तार

चंडीगढ़(सत्ता संदेश)-पंजाब के छ्वत्रक्क गौरव यादव ने बताया कि फिरोजपुर पुलिस ने 22 चद्द से ज़्यादा हेरोइन, हथियार और ड्रग मनी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने ट्वीट किया, एक बड़ी कामयाबी में, फिरोजपुर पुलिस ने एक नार्को-आर्म्स मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और 22 Kg 295 gm हेरोइन, मैगज़ीन और कारतूस के साथ 2 ग्लॉक पिस्टल, एक कार और` 2.05 लाख ड्रग मनी बरामद की है।

एक FIR दर्ज कर ली गई है और आगे और पीछे के लिंक का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

मंत्री संजीव अरोड़ा की मीटिंग को लेकर ममता आशू ने पंजाब सरकार को घेरा

कहा, नगर निगम लुधियाना की हाउस मीटिंग का 25 मिनट चलना समझ से परे

लुधियाना (सत्ता संदेश)-पूर्व पार्षद एवं पूर्व कैबिनट मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ममता आशु ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट सांझा करते हुए स्थानीय सरकार (लोकल गवर्नमेंट) की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने हालिया मीटिंग की एक तस्वीर जारी करते हुए शहर के विकास कार्यों में बाहरी दखलअंदाजी और 'डमी कल्चर' पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता आशु ने अपनी पोस्ट में लिखा कि स्थानीय सरकार की मीटिंग में लुधियाना नगर निगम की फाईल टेबल पर रखी गई है और इस विभाग के मिनिस्टर संजीव अरोड़ा बड़े गर्व से यह दावा कर रहे हैं कि निगमों के विकास से जुड़े एजेंडे पास कर दिए गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गत सोमवार को हुई नगर निगम लुधियाना की हाउस मीटिंग मात्र 25 मिनट के भीतर ही समाप्त हो गई, जिसमें सॉलिड वेस्ट

मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को आनन-फानन में मंजूरी दे दी गई। ममता आशु ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लुधियाना वासियों से कहा कि वे साफ देख सकते हैं कि इस मीटिंग का संचालन दिल्ली से आए %बॉस' कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह वास्तव में पंजाब के विकास का एजेंडा है या फिर दिल्ली द्वारा तैयार किया गया 'विकास की चौगुनी रफ्तार' का कोई बाहरी वर्जन? उन्होंने विशेष रूप से मिनिस्टर संजीव अरोड़ा के दाएं और बाएं बैठे दो व्यक्तियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'डमी' करार दिया। ममता आशु ने पूछा कि ये दोनों व्यक्ति पंजाब के लोकल बॉडी विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग में आखिर किस पद पर तैनात हैं और मंत्री जी को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने रोज गार्डन टैंडर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी अभी तक बड़े अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है।

रक्तदान करने वाले डोनर ही 22 से 29 मार्च के नाईट क्रिकेट टूर्नामैंट खेल पाएंगे-जसवंत सिंह

लाइफ लाइन फाऊंडेशन की ओर से मानवता की सेवा को समर्पित कैंप 17 फरवरी को

लुधियाना (सत्ता संदेश)-लाइफ लाइन फाऊंडेशन की ओर से मानवता की सेवा को समर्पित 17 फरवरी को सेखेवाल रोड़ स्थित लाइफ लाइन हैल्थ केयर सैंटर में रक्तदान, आंखों, दांतो व हड्डियों का चैकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप के संबंध में फाऊंडेशन के वालंटियर्स की ओर से शिवपुरी गली नं. 9 गनीव गारमैंट्स के हरसिमरन सिंह के दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में फाऊंडेशन के वालंटियर्स की ओर से कैंप के साथ-साथ 22 से 29 मार्च तक आयोजित होने वाले नाइट क्रिकेट टूर्नामैंट के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में वालंटियर्स को संबोधित करते हुए जसवंत सिंह व सतविंदर सिंह रिक्की ने बताया कि 17 फरवरी को आयोजित होने वाले रक्तदान कैंप में जो डोनर ब्लॅड डोनेट करेगा, वही डोनर नाइट क्रिकेट टूर्नामैंट का खिलाड़ी बन पाएगा, इसलिए 'यादा से 'यादा लोग कैंप में रक्तदान करें। उन्होंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव मैंबर 'यादा से 'यादा डोनर को जोड़ेगा, उसे ही कैप्टनशिप का मौका दिया जाएगा। बैठक में फाऊंडेशन के वालंटियर्स संजीव कपूर व ललित कपूर ने बताया कि संस्था की ओर से 17 फरवरी को सुबह 10.00 बजे से लेकर 5.00 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डी.एम.सी., सी.एम.सी., एस.पी.एस., फोर्टिस व मोहनदेई ओसवाल अस्पताल के ब्लॅड बैंक की टीमे हिस्सा लेंगी। बैठक में फाऊंडेशन के वालंटियर्स नरिंदर सिंह विक्की व हरसिमरन सिंह ने बताया कि कैंप को लेकर संस्था की ओर से वालंटियर्स की ड्यूटियां लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कैंप में आंखों का चैकअप करवाने वाले मरीजों को चश्में, दवाइयां भी दी जाएगी। बैठक में फाऊंडेशन के वालंटियर्स डा. अनिल तनेजा व चेतन टंडन ने बताया कि कैंप में जिन मरीजों को डॉक्टरों की ओर से आप्रेशन के लिए चुना जाएगा, उन मरीजों के आप्रेशन फाऊंडेशन के वालंटियर्स की ओर से करवाए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों को इस कैंप का लाभ लेने की अपील की। बैठक में जसवंत सिंह, नरिंदर सिंह विक्की, हरसिमरन सिंह, सतविंदर सिंह रिक्की, ललित कपूर, संजीव कपूर, डॉ. अनिल तनेजा, चेतन टंडन आदि मौजूद रहे।

ठेकेदारों की आपसी खींचतान व शिकायतों की भेंट चढ़ी 133 करोड़ रुपये की सड़क योजना!

चार प्रोजैक्टों पर कानूनी सलाह के बाद ब्रेक, दो अन्य प्रोजैक्ट गहन जांच कारण ठंडे बस्ते में

लुधियाना (सत्ता संदेश)-शहर की जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लाई गई 133 करोड़ की विशेष सहायता योजना अब ठेकेदारों की आपसी खींचतान और शिकायतों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। नगर निगम द्वारा प्रस्तावित 20 में से 12 टैंडरों की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन आठ अहम प्रोजैक्ट विवादों, आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच के जाल में उलझकर अटक गई हैं। नगर निगम ने इस योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों के निर्माण और मजबूतीकरण का खाका तैयार किया था ताकि वर्षो से खराब सड़कों से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर आ सके। 12 टैंडरों की वित्तीय बोलियां खुल चुकी हैं, जिसे निगम आंशिक सफलता बता रहा है लेकिन शेष आठ टैंडरों पर ठेकेदारों ने एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक कई ठेकेदारों ने टैंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए नगर निगम को नोटिस तक भेजा गया हैं। तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन शिकायतों के चलते चार प्रोजेक्टों पर कानूनी सलाह लेने के बाद ब्रेक लगा दिया गया है। दो अन्य प्रोजेक्ट ठेकेदारों की साख और कागजात की गहन जांच के कारण फिलहाल ठंडे बस्ते में हैं, जबकि

बाकी भी आपसी आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ी हुई हैं। नगर निगम के अधिकारी भले ही इसे पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि सड़क सुधार का सपना कागजों और फाइलों में उलझता जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में किसी कानूनी अड़चनों या पक्षपात के आरोप से बचने के लिए हर दस्तावेज की बारीकी से जांच जरूरी है, ताकि सरकारी खजाने से खर्च होने वाली भारी-भरकम राशि का दुरुपयोग न हो। एक समाज सेवी कहा कि 133 करोड़ के इस पैकेज में शामिल कई सड़कें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में प्रोजैक्टों का लटकना आम जनता की परेशानी को और बढ़ा रहा है। रोजाना सफर करने वाले लोगों ने धीमी गति से किए जा रहे विकास कार्यों से ही संतोष जताना पड़ रहा है, लेकिन लंबित टेंडरों पर सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ठेकेदारों की खींचतान और प्रशासनिक देरी का खामियाजा आखिर जनता ही भुगत रही है। अब निगाहें नगर निगम पर टिकी हैं कि वह विवादों का जल्द निपटारा कर रुके हुए प्रोजेक्टों को हरी झंडी देता है या फिर सड़क प्रोजेक्ट के लिए बनाई योजना उल्झन में ही रह जाएगी। दूसरी तरफ सुपरिटैंडिंग इंजीनियर शाम लाल गुप्ता ने दावा किया कि टैंडर प्रक्रिया जारी है और कामं जल्द शुरू होगा। उनके अनुसार, सभी टैंडर प्रक्रिया में हैं और कुछ टैंडर शीघ्र अलाट किए जाएंगे, जिसके बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

देश के लिए शहादत देने वाला शहीद हमेशा अमर रहता है-डिंपल राणा

लुधियाना (सत्ता संदेश)-शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले को काले दिवस के रुप में मनाते हुए शहीद हुए सी.आर.पी.एफ के 40 जांबाजों के बलिदान को स्मरण कर भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सेना की 3 जैक एल.आई के जवानों ने शस्त्र उलटे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ बलिदानी को सलामी दी। प्रि.जसकरणजीत सिंह काहलों की अध्यक्षता में सी.आर.पी.एफ की 75 बटालियन के कांस्टेबल मनिन्द्र सिंह का सातवें बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब के अध्यक्ष डिम्पल राणा व सी.जी.एम (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) कम-सचिव जिला कानूनी ऑथारिटी गुरदासपुर हरप्रीत सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा 25 मैक यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल विश्वानाथ सीजी, 3 जैक एल.आई यूनिट से लेफ्टीनेंट बी.एस नेगी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। डिंपल राणा ने सात वर्ष पहले पुलवामा में हुए आंतकी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल मनिन्द्र सिंह सहित 40 सी.आर.पी.एफ जवानो की शहादत को नमन करते हुए कहा मनिन्द्र जैसे जांबाजों के शौर्य व अमिट बलिदानों का देश सदैव कर्जदार रहेगा । देश के लिए शहादत देने वाला शहीद हमेशा अमर रहता है। मातृ भूमि के लिए शहादत देने वाला शहीद राष्ट्र का सरमाया होते हैं जो देश अपने वीर सैनिकों के बलिदान की कद्र नहीं करते उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सी.जी.एम गुरदासपुर हरप्रीत सिंह ने डिंपल राणा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा शहीद किसी जाति व धर्म के नहीं बल्कि राष्ट्र के नायक है। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब के चेयरमैन ठाकुर दविन्द्र सिंह दर्शी, कार्यकारिणी अध्यक्ष संत सिंह राणा, डी.एस राणा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविन्द्र सिंह विक्की प्रेस सचिव बिट्टा काटल, बी.एस.एफ की 24 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट ए.के पवन, शहीद के पिता सतपाल अत्री, भाई लखवीश सिंह, भाभी ममता, बहनें शबनम, शीतल व गगन, बहनोई अशोक कुमार, राजिंदर सिंह व संदीप कुमार, भांजा आकाश सहित अन्य भी उपस्थित रहे।

लुधियाना के फ्लाई ओवर पर ओवरलोडेड ट्रक पलटा

सैकड़ों बोरी गेहूं ने मचाया तबाही का आलम

लुधियाना (सत्ता संदेश)-महानगर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले भारत नगर चौक फ्लाई-ओवर पर आज सुबह उस समय चीख-पुकार मच गई, जब एक ओवरलोडेड ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक में लदी गेहूं की सैकड़ों बोरियां फ्लाई-ओवर से नीचे खड़ी गाड़ियों और दुकानों पर जा गिरीं। इस हादसे में कई कारें, मोटरसाइकिल और दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका है।

घटना सुबह करीब सवा 8 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फ्लाई-ओवर से गिरती बोरियों की चपेट में कई वाहन आ गए। मौके पर मौजूद लोगों में इस बात को लेकर भारी दहशत है हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा कुछ समय बाद होता, तो भीड़ ज्यादा होने के कारण बड़ी जनहानि हो सकती थी।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि घटना सवा 8 बजे हुई और सवा 9 बजे तक भी कोई पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 112 नंबर पर तुरंत सूचित किया था, लेकिन मदद पहुंचने में काफी देरी हुई। इसी बीच, मौके का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर वहां से फरार होने में कामयाब रहा।

चंडीगढ़ की राजनीति में फिर सक्रिय हुईं किरण खेर

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-चंडीगढ़ की पूर्व सांसद किरण खेर एक बार फिर शहर की राजनीति में सक्रिय नजर आने लगी हैं। लगातार दो बार लोकसभा में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के बाद 2024 के आम चुनाव में उनका टिकट कट गया था। उनकी जगह भाजपा ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन मुकाबले में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के बाद किरण खेर ने कुछ समय के लिए चंडीगढ़ से दूरी बना ली थी, लेकिन अब उनकी सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

हाल ही में वह धनास की मिल्क कॉलोनी में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचीं। यह ग्राउंड उनके सांसद कार्यकाल के दौरान एमपीलैड फंड से बना था। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद कुलजीत संधू, भाजपा नेता रामबीर भट्टी, मनोनीत पार्षद सतिंदर सिंह सिद्धू सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में किरण खेर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि ÷कई बार पूर्व सांसद मौजूदा सांसद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए लोग देखने आ जाते हैं।'

लुधियाना बस स्टैंड के पास होटल में बवाल, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

लुधियाना (सत्ता संदेश)- बस स्टैंड के पास स्थित 'होटल 7 एस्केप' में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने सरेआम हवाई फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। होटल मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता मोहित यादव ने पुलिस को बताया कि 14 फरवरी की रात वह होटल की रिसेप्शन पर मौजूद था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति, जो पूरी तरह शराब के नशे में धुत लग रहा था, होटल पहुँचा और कमरे की मांग करने लगा। होटल स्टाफ ने नियमानुसार जब उससे उसका आईडी प्रूफ मांगा, तो वह टालमटोल करने लगा। टोकने पर आरोपी तैश में आ गया और होटल मालिक व स्टाफ के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी शुरू कर दी।

मोहाली के फोर्टिस में पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की सफल सर्जरी, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह को मोहाली के एक निजी अस्पताल में घुटने की रिप्लेसमेंट (प्रत्यारोपण) सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मोहाली फोर्टिस अस्पताल ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि सिंह का 10 फरवरी को घुटने का सफल ऑपरेशन हुआ था। इसमें कहा गया है कि हड्डी रोग निदेशक डॉ. हरसिमरन सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम ने यह प्रक्रिया संपन्न की। डॉ. हरसिमरन सिंह ने कहा, 'कैप्टन अमरिंदर सिंह की सर्जरी के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और ऑपरेशन के बाद वह जल्दी ठीक हो गए। ऑपरेशन के बाद उन्हें चलने में कोई दर्द नहीं था और उन्हें मोहाली फोर्टिस अस्पताल से संतोषजनक स्थिति में छुट्टी दे दी गई।'

गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद रिहा हुए लुधियाना के इनफ्लुएंसर हनी सेठी

लुधियाना (सत्ता संदेश)-लुधियाना के खन्ना व दोराहा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हनी सेठी को नशे के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद हनी सेठी को पुलिस ने रिहा कर दिया।

NDPS के तहत हुआ था केस दर्ज

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पहले उनके खिलाफ नशे से संबंधित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस की पूछताछ और डोप टेस्ट रिपोर्ट में नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि के बाद उस पर NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

यह कार्रवाई दोराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खन्ना के समीप की गई, जहाँ पुलिस को हनी सेठी की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर शिकायतें मिली हुई थीं। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने उसे रोका और सांकेतिक आधार पर मेडिकल जांच कराने का निर्णय लिया, जिसमें नशे का उपभोग साबित हुआ।

मेडिकल परीक्षण में नशा करने की पुष्टि

दोराहा थाना के एसएचओ आकाश दत्त ने बताया कि पुलिस को सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यवहार देखने के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की पुष्टि होते ही पुलिस ने कानूनी रूप से गिरफ्तार किया। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की गहनता को देखते हुए आगामी जांच जारी है और आवश्यक पहल आगे भी की जाएगी।

सोशल मीडिया पर विवादित रहे हनी सेठी

हनी सेठी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा है और उसके कई वीडियो व पोस्टों पर पहले भी विवादित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उसकी गिरफ़्तारी के बाद से ही खन्ना और दोराहा के आसपास इसका खूब चर्चा हो रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और कानून के उल्लंघन पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी।

शादी से एक दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, 8 महीने पहले हुई थी सगाई

अमृतसर (सत्ता संदेश)- गांव खापड़खेड़ी में शगुन लगने से एक दिन पहले दुल्हन घर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। लड़का परिवार ने पुलिस थाना घरिंडा की पुलिस चौकी खासा में लड़की के परिवार के खिलाफ शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक मामला छेहरटा स्थित खापड़खेड़ी गांव का है। जहां 31 वर्षीय हरप्रीत सिंह की शादी डर्मा वाला बाजार सुल्तान विंड रोड की रहने वाली किरणदीप कौर के साथ उनकी 8 महीने पहले सगाई हुई थी। परिजनों ने फरवरी में शादी तय की थी, जिसकी बारात 15 फरवरी को जानी थी और घर पर शादी की तैयारी जोरों पर चल रही थी। 14 फरवरी को शगुन लगने की रस्में होने वाली थी, लेकिन 14 फरवरी को सुबह करीब 5 बजे लड़की के परिजनों का फोन आ गया कि उनकी बेटी किरणदीप कौर घर से लापता हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की परिवार ने लड़की का किसी के साथ चक्कर होने के कारण परिवार पिछले आठ महीनों से शादी की तारीख को लेकर टालमटोल करते आ रहे थे।

7 करोड़ की महाठगी का मामला

कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा कर लूटने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

लुधियाना (सत्ता संदेश)-महानगर के एक नामी कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करीब 7 करोड़ रुपए की मोटी रकम ठगने वाले गिरोह के एक मुख्य सदस्य को लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर सैल की टीम ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी अर्पित राठौड़ को केंद्रीय जेल कपूरथला से प्रोडक्शन वारंट लेकर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी को कानूनी पचड़ों और गिरफ्तारी का ऐसा खौफ दिखाया कि पीड़ित ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन शातिर ठगों के हवाले कर दी। पुलिस अब इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है। ए.सी.पी. मुराद जसवीर सिंह और इंस्पेक्टर सतवंत सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला साल 2024 से जुड़ा है जिसमें ठगों ने कारोबारी को यह विश्वास दिलाया था कि वह किसी बड़े अपराध में शामिल है और उसे बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए की चपत लगा दी।

हालांकि, इससे पहले पुलिस ने कई ओर आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया था। अब पुलिस आरोपी अर्पित राठौड़ को लेकर आई है जोकि कपूरथला जेल में बंद था। पुलिस ने आरोपी का रिमांड हासिल किया है। रिमांड के दौरान पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ में इस अंतर्राज्यीय गिरोह के अन्य सदस्यों और पैसे के लेन-देन से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकेंगी। साइबर सैल के अधिकारी मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर इस ठगी के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने आम जनता को सतर्क रहने की विशेष अपील जारी की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है और सरकारी एजेंसियां कभी भी वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तार या डराती-धमकाती नहीं हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि यदि उन्हें किसी अनजान नंबर से इस तरह की संदिग्ध कॉल या मैसेज आता है तो घबराने की बजाय तुरंत साइबर क्राइम हैल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें या अपने नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करें।

आज का विचार सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने विचार और कर्म बदलते हैं, तभी समाज भी बदलता है। – महात्मा गांधी

सम्पादकीय

बांग्लादेश का जनादेश:

लोकतंत्र की वापसी और तारिक रहमान की अग्निपरीक्षा

बांग्लादेश के आम चुनावों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत देकर स्पष्ट कर दिया है कि वह किस तरह का भविष्य चाहती है। संसद की 300 में से 212 सीटों पर जीत न केवल सत्ता परिवर्तन है, बल्कि यह उस विचारधारा पर भी जनमत है जो लोकतांत्रिक, समावेशी और विकासोन्मुख बांग्लादेश की पैरवी करती है।

17 वर्षों का निर्वासन काटने के बाद तारिक रहमान का लंदन से ढाका तक का सफर असाधारण रहा है। परिस्थितियां बदलीं, सत्ता का संतुलन बदला और आज उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग औपचारिकता माना जा रहा है। लेकिन यह जनादेश जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। जनता ने कट्टरता, हिंसा और अस्थिरता के विरुद्ध वोट दिया है–अब उस भरोसे को कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

चुनाव नतीजों ने उन इस्लामवादी ताकतों को भी सीमित कर दिया है, जो बांग्लादेश को शरिया आधारित 'मुस्लिम राष्ट्र' बनाने का दावा कर रही थीं। जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 74 सीटों तक सिमटना पड़ा। यह संकेत है कि बहुसंख्यक मतदाता धर्म के नाम पर राजनीति से आगे बढ़कर रोज़गार, सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

यह जनादेश एक कठिन और हिंसक पृष्ठभूमि में सामने आया। मतदान के दौरान कई इलाकों में झड़पें हुईं, बूथों पर हमले हुए और फर्जी मतदान के आरोपों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दी। इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय–खासतौर पर हिंदू मतदाताओं–ने बड़े पैमाने पर भागीदारी निभाई। मंदिरों और प्रतीकों पर हमलों के डर के बीच भी लोकतंत्र के पक्ष में वोट पड़ना बताता है कि नागरिक समाज की जड़ें अब भी मज़बूत हैं। महिलाओं की भारी भागीदारी ने भी संकेत दिया कि मतदाता संकीर्णता नहीं, बल्कि अवसर और समानता चाहते हैं।

बीएनपी की वापसी लगभग दो दशक बाद हुई है। इस दौरान देश ने राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक दबाव और संस्थागत अविश्वास देखा। अब नई सरकार से अपेक्षा है कि वह कानून-व्यवस्था बहाल करे, अर्थव्यवस्था को गति दे और कट्टरपंथ पर सख्त नियंत्रण रखे। यह भी ज़रूरी है कि सत्ता में आते ही बदले की राजनीति से बचा जाए और संस्थानों की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित किया जाए।

क्षेत्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी यह बदलाव अहम है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है। नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई बधाई और सहयोग का संकेत बताता है कि 'नया बांग्लादेश' क्षेत्रीय स्थिरता में भागीदार बन सकता है। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में बांग्लादेश की भूमिका केंद्रीय है–सड़क, रेल और जलमार्ग की कनेक्टिविटी परियोजनाएं, ऊर्जा सहयोग और व्यापार विस्तार दोनों देशों के हित में हैं।

साथ ही, ढाका की विदेश नीति में संतुलन साधना भी जरूरी होगा–पाकिस्तान के प्रभाव, उसकी खुफिया एजेंसी की सक्रियता और चीन की बढ़ती दिलचस्पी जैसे सवाल अब भी बने हुए हैं। बीएनपी ने अतीत में पाकिस्तान से दूरी की बात की है; अब उसे व्यवहार में दिखाना होगा। एक और संवेदनशील मुद्दा 'इंडिया आउट' जैसे अभियानों का रहा है–नई सरकार के लिए यह समय है कि वह बयानबाज़ी से आगे बढ़कर भरोसे का वातावरण बनाए।

अंततः, यह जनादेश किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं, बल्कि उस उम्मीद का है कि बांग्लादेश हिंसा और कट्टरता से बाहर निकलकर स्थिरता, विकास और सह-अस्तित्व की राह पकड़े। तारिक रहमान के सामने अवसर भी है और अग्निपरीक्षा भी–यदि वे लोकतांत्रिक मूल्यों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, तो यह जीत वास्तव में 'नए बांग्लादेश' की नींव बन सकती है।

जितेंद्र कुमार,
सम्पादक

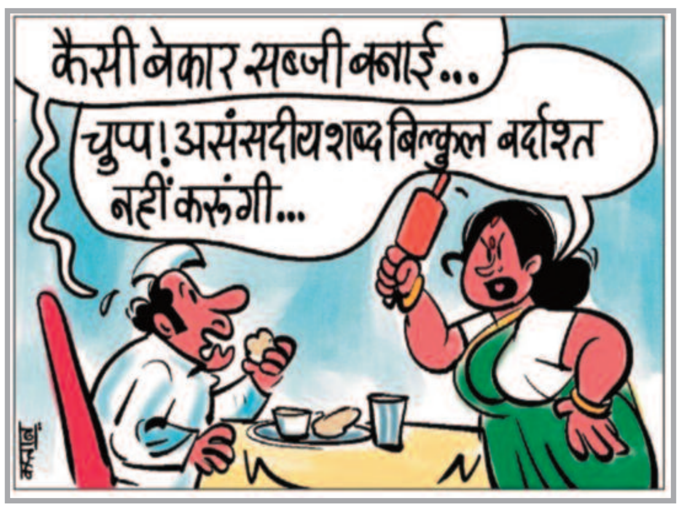
कैसी बेकार सब्जी बनाई...
चुप्प! असंसदीय शब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी...
कमाल

सत्ता संदेश
R.N.I. No. PBHIN/25/A4135
पब्लिशर, एडिटर, मालिक जितेंद्र कुमार और प्रिंटर अश्मीत सिंह ने न्यूज़पेपर 'सत्ता संदेश' (हिंदी साप्ताहिक), ने मुंजाल प्रिंटर्स 1558/1, अमरपुरा, माता वाली गली, सिविल हस्पताल के पास, लुधियाना, पंजाब – 141008 से छपवाकर अपने आफिस पीएल 42, वर्धमान पार्क, चंडीगढ़ रोड, मुंडियां कलां, लुधियाना, पंजाब – 141015। से प्रकाशित किया।

Publisher, Editor, Owner JITENDER KUMAR and Printer ASHMEET SINGH Newspaper Title 'SATTA SANDESH' (Hindi Weekly), Printed at MUNJAL PRINTERS 1558/1, AMARPURA MATA WALI GALI, NEAR CIVI HOSPITAL, LUDHIANA, PUNJAB - 141008 and Published from PL 42, VARDHMAN PARK, CHANDIGARH ROAD, MUNDIAN KALAN, LUDHIANA, PUNJAB - 141015.
M. +91 92162 42177
Email : sattasandesh25@gmail.com

रण में प्रदर्शित दुनिया का सबसे विशाल खादी तिरंगा:

आत्मनिर्भर 'नये भारत' की गाथा

लेखक
श्री मनोज कुमार
अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार

कच्छ का सफेद रण- जहाँ धरती और आकाश मानो एक-दूसरे में विलीन होते दिखाई देते हैं-आज केवल प्राकृतिक आश्चर्य का स्थल नहीं, बल्कि नये भारत के बदलते आत्मविश्वास का सजीव प्रतीक बन चुका है। इसी विराट विस्तार के बीच, हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, दुनिया के सबसे विशाल प्रतीकात्मक खादी तिरंगे का भव्य एवं दिव्य प्रदर्शन किया गया। यह केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वदेशी परंपरा, राष्ट्रीय संकल्प और समकालीन भारत की विकास-दृष्टि की सशक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी।

इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य के साक्षी देश के कारीगर, सुरक्षा बलों के जवान और अनेक नागरिक बने। ये भी अपने आप में नया कीर्तिमान बना कि देशभर के लाखों खादी कारीगरों ने वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देखकर इतिहास रच दिया। यह क्षण इस बात को रेखांकित करता है कि राष्ट्र निर्माण किसी एक संस्था या वर्ग का कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। यह तिरंगा केवल कपड़े का विस्तार नहीं, बल्कि विचार का विस्तार है। खादी, जिसे कभी स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा कहा गया, आज आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा के रूप में पुनर्परिभाषित हो रही है। महात्मा गांधी का यह कथन-'खादी भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है'- समकालीन भारत में एक नए अर्थ के साथ जीवंत दिखाई देता है।

इस राष्ट्रीय पुनर्जागरण को समझना हो तो भुज की ओर देखना पर्याप्त है। विनाशकारी भूकंप ने कभी इस शहर को गहरे घाव दिए थे, किंतु संकट के उसी क्षण में एक दीर्घदर्शी दृष्टि ने पुनर्निर्माण को केवल आवश्यकता नहीं, अवसर के रूप में देखा। तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भुज का पुनर्जन्म हुआ- योजनाबद्ध शहरीकरण, सुदृढ़ अधोसंरचना और सामुदायिक पुनर्स्थापन के माध्यम से।

Khadi India
#IconicKhadiTiranga

पुनर्निर्माण के 25 वर्ष बाद, भुज केवल खड़ा नहीं है; वह आगे बढ़ रहा है। वह इस सत्य का प्रमाण है कि जब नेतृत्व में स्पष्टता और संकल्प हो, तो आपदा भी विकास की प्रस्तावना बन सकती है।

भौगोलिक रूप से सीमांत क्षेत्र में स्थित होने के कारण भुज का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ विकास और सुरक्षा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। तैनात भारतीय सैनिकों की सतर्क उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति उसकी सामरिक स्थिरता पर ही टिकती है। 'ऑपरेशन सिंदूर' की भावना से प्रेरित विश्व के सबसे विशाल प्रतीकात्मक खादी तिरंगे को दी गई सलामी वस्तुतः उन अनगिनत वीरों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता है, जिनके त्याग से विकास की धारा निर्बाध बहती है।

यदि तिरंगा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, तो खादी उस गौरव की आत्मा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खादी को अतीत की स्मृति से निकालकर भविष्य की रणनीति का हिस्सा बनाया है। उनके शब्दों में- 'खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का विचार और जन-आंदोलन है।'

इस जन-आंदोलन ने पूरे भारत को आंदोलित किया है। परिणाम सामने है। आज ग्राम स्वराज की अवधारणा व्यवहारिक अर्थशास्त्र में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 1.70 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और शीघ्र ही 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने की ओर अग्रसर है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि इस क्षेत्र ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है- एक ऐसा परिवर्तन जो ग्रामीण भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशिक्षण, टूल्स वितरण और स्थानीय कौशल को प्रोत्साहन देने वाली पहलों ने विकास का एक विकेंद्रीकृत मॉडल प्रस्तुत किया है। पिछले 11 वर्षों 2.88 लाख से अधिक मशीनों और टूलकिट्स के वितरण ने यह साफ संकेत दिया है कि भारत का विकास अब महानगरों तक सीमित नहीं; वह गाँवों, कुटीर उद्योगों और पारंपरिक कारीगरों के माध्यम से व्यापक सामाजिक आधार प्राप्त कर रहा है।

इस परिवर्तन के केंद्र में श्रम की गरिमा है। खादी कारीगरों की पारिश्रमिक 15 रुपये प्रति लच्छा तक पहुँच चुकी है और इसे 20 रुपये प्रति लच्छा से आगे ले जाने का संकल्प इस बात का द्योतक है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ आय वृद्धि के साथ सम्मान की स्थापना भी है। यह परिघटना वस्तुतः एक उभरते 'आर्टिजन युग' का संकेत देती है- एक ऐसा कालखंड, जिसमें परंपरा और प्रौद्योगिकी मिलकर नई समृद्धि का निर्माण कर रहे हैं।

डिजिटल युग में प्रतीकों की शक्ति और भी बढ़ जाती है। #IconicKhadiTiranga का सोशल मीडिया पर 20 मिलियन से अधिक व्यूज़ प्राप्त करना केवल लोकप्रियता का संकेत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का द्योतक है। विशेषकर Gen-Z का इस प्रतीक से जुड़ना बताता है कि नई पीढ़ी वैश्विक आकांक्षाओं के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी उतनी ही दृढ़ता से स्वीकार करना चाहती है।

कच्छ के सफेद रण में भव्य और दिव्य रूप में आलोकित होता यह तिरंगा अंततः हमें एक व्यापक सत्य की ओर ले जाता है- राष्ट्र निर्माण किसी एक नीति, एक परियोजना या एक समयखंड का परिणाम नहीं होता। वह दृष्टि, निरंतरता और सामूहिक विश्वास से निर्मित होता है। जब विरासत को सम्मान मिलता है, जब विकास समावेशी होता है, जब सीमाएँ सुरक्षित होती हैं और जब नेतृत्व भविष्य को देखने का साहस रखता है-तब परिवर्तन एक घटना नहीं, एक युग बन जाता है।

भुज का पुनर्जागरण, खादी का पुनरुत्थान और ग्राम स्वराज की नई ऊर्जा मिलकर जिस भारत की रचना कर रहे हैं, वह संभावनाओं का नहीं, उपलब्धियों का भारत है- आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और निर्णायक। सफेद रण में विराजमान प्रतीकात्मक खादी तिरंगा इसी भारत का ध्वजवाहक है- एक ध्वज, जो केवल हवा में नहीं लहराता, बल्कि एक राष्ट्र की चेतना को वैश्विक पटल पर नयी पहचान देता है।

एप्स्टीन फ़ाइल्स: जब सत्ता, पैसा और अपराध एक ही दायरे में मिलते हैं

जितेन्द्र सिंह रावत
पत्रकारिता विभाग, डीएवी यूनिवर्सिटी,

जेफरी एप्सटीन से जुड़ी 'एप्स्टीन फ़ाइल्स' आज के समय के सबसे रहस्यमय और विवादित मामलों में गिनी जाती हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर सत्ता, धन और प्रभाव के उस तंत्र को उजागर करता है, जहाँ सच अक्सर दबा दिया जाता है।

जेफ़री एप्स्टीन एक धनी फाइनेंसर था, जिसने बहुत कम समय में अमीरों और ताक़तवर लोगों के बीच अपनी खास पहचान बना ली। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। जांच के दौरान सामने आए दस्तावेज़, गवाहों के बयान, कोर्ट रिकॉर्ड और गोपनीय सूचियों को ही आम भाषा में ÷एप्स्टीन फ़ाइल्स÷ कहा जाने लगा। इन फ़ाइल्स ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कानून वास्तव में सभी के लिए समान है।

एप्स्टीन फ़ाइल्स को लेकर सबसे बड़ा विवाद उन कथित नामों को लेकर है, जिनका संबंध किसी न किसी रूप में एप्स्टीन से बताया गया। इनमें राजनेताओं, उद्योगपतियों और प्रभावशाली सामाजिक हस्तियों के नाम सामने आने के दावे किए गए। हालांकि, इनमें से कई नामों पर कानूनी रूप से अपराध सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह जरूर उठा कि क्या प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को सीमित रखा गया।

इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में रही। पहले हुए समझौते, हल्की सज़ाएँ और बाद में जांच की धीमी गति ने आम लोगों के मन में अविश्वास पैदा किया। जब एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, तब उम्मीद जगी कि शायद इस बार पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हिरासत में उसकी मौत ने पूरे मामले को और उलझा दिया।

आधिकारिक तौर पर एप्स्टीन की मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक, निगरानी कैमरों का काम न करना और जेल कर्मचारियों की लापरवाही जैसी बातों ने कई सवाल खड़े किए। इसी वजह से ÷एप्स्टीन फ़ाइल्स÷ आज भी अधूरी सच्चाई का प्रतीक बनी हुई हैं।

यह मामला मीडिया की भूमिका पर भी गहन चर्चा को जन्म देता है। कुछ मीडिया संस्थानों ने लगातार सवाल उठाए, दस्तावेज़ खंगाले और पीड़ितों की आवाज़ को सामने लाने की कोशिश की। वहीं, आलोचकों का मानना है कि मुख्यधारा का मीडिया लंबे समय तक इस मुद्दे से दूरी बनाए रहा, जिससे सच्चाई सामने आने में देर हुई।

एप्स्टीन फ़ाइल्स का सबसे दुखद पहलू पीड़ितों की कहानी है। इन फ़ाइल्स के पीछे वे लड़कियाँ और महिलाएँ हैं, जिनका शोषण हुआ और जिनकी आवाज़ को वर्षों तक अनसुना किया गया। यह मामला हमें याद दिलाता है कि जब अपराधी ताक़तवर होता है, तब पीड़ित को न्याय पाने के लिए कई गुना संघर्ष करना पड़ता है।

एप्स्टीन फ़ाइल्स केवल अतीत का एक आपराधिक मामला नहीं हैं, बल्कि यह वर्तमान समाज के लिए चेतावनी हैं। यह चेतावनी कि पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच और जवाबदेही के बिना न्याय अधूरा रह जाता है। अगर लोकतंत्र और कानून को सच में मजबूत बनाना है, तो हर तरह के दबाव से ऊपर उठकर सच को सामने लाना ही एकमात्र रास्ता है।

कहानी

'बुद्धिमान हंस'

एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बहुत स्थाना हँस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करके 'ताऊ' कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही-सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया।

ताऊने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, 'देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी।' एक युवा हंस हंसते हुए बोला, 'ताऊ, यह छोटी-सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी?' स्याने हंस ने समझाया, %आज यह तुम्हें छोटी-सी लग रही है। धीरे-धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा, तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढने् के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे।'

दूसरे हंस को यकीन न आया, 'एक छोटी-सी बेल कैसे सीढी बनेगी?'

तीसरा हंस बोला, 'ताऊ, तुम तो एक छोटी-सी बेल को खींचकर 'यादा ही लंबा कर रहे हो।'

एक हंस बड़बड़ाया, 'यह ताऊ अपनी यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है।'

इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहां थी? समय बीतता रहा। बेल लिपटते-लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गईए जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था।

सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी।

एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए।

जब वे जाल में फंस गए और फडफ़ड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आपको कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था।

एक हंस ने हिम्मत करके कहा, 'ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो।'

दूसरा हंस बोला, 'इस संकट से निकालने की तरकीब त ही हमें बता सकता है। आगे तू हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे।'

सभी हंसों ने हामी भरी तब ताऊ ने उन्हें बताया, 'मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना।'

सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया, जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक् होकर देखता रह गया।

सीख-बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।

पंजाब में रेव पार्टियों के बढ़ते चलन के बीच खूब फल-फूल रहा है नशा व देह-व्यापार का धंधा

बड़े शहरों में सोशल मीडिया के जरिए बुकिंग और होटलों में अंदरखाते होते हैं सौदे!

अमृतसर (सत्ता संदेश)-जैसे-जैसे दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, वैसे ही देह व्यापार में भी अब आधुनिकता आ चुकी है। पंजाब के बड़े शहरों में अब रेव पार्टियों के बढ़ते चलन के बीच नशा व देह-व्यापार का धंधा जमकर फल-फूल रहा है। विगत समय लुधियाना के एक होटल में बड़े घरानों के लोगों द्वारा अश्लील डांस व सैक्स थीम पार्टियों के खुलासे से जहां हड़कंप मच गया था, वहीं अमृतसर के होटलों में भी अंदरखाते गुपचुप ढंग से ऐसी ही थीम पार्टियों का चलन अंदरखाते हो रहा है। हालांकि इस बारे में पुलिस ने भी काफी तत्परता दिखाते हुए कई होटलों में रेड कर मामले दर्ज किए हैं, परंतु इसके बावजूद यह देह व्यापार का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर नजर दौड़ाई जाए तो पुलिस की अधिकांश रेड जब होटलों व रेस्टोरेंट पर पड़ती है तो ज्यादातर हुक्का बार के मामले पकडने तक ही सीमित नजर आती है। ऐसा नहीं है कि अमृतसर के होटलों में अंदरखाते रेव पार्टियों का चलन नहीं होता। आजकल सोशल साइट्स व फेसबुक पर ऐसे कई अकाउंट मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से इन रेव व थीम पार्टियों की बुकिंग अलग-अलग शहरों के होटलों में की जाती है। आमतौर पर सभी को ज्ञात है कि अलग-अलग थीम पर रखी गई इन रेव पार्टियों में नशा व देह व्यापार जमकर होता है। ऐसी पार्टियों के लिए लड़कियां भी बाहरी शहरों से लाई जाती हैं। एक ओर जहां अमृतसर में बड़े स्तर पर फैल चुके देह व्यापार के धंधे को रोकने के लिए महानगर की पुलिस द्वारा मुहिम चलाई गई और काफी सख्ती की गई, बावजूद इसके यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले पुलिस प्रशासन ने इस देह व्यापार के कुछ संचालकों को पकड़ा था, जिससे इस अवैध धंधे में कुछ कमी आई थी, परंतु वर्तमान में फिर से देह व्यापार काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है। जानकारी के अनुसार महानगर में दर्जनों सोशल साइट्स के ग्रुप व एप्स मौजूद हैं, जो इस धंधे को अंदरखाते चलाते हैं। पता चला है कि ऐसी महिलाओं की कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंच होती है। इसके कारण ये महिलाएं उनकी शरण में उक्त धंधा बेखौफ होकर चलाती हैं। इन महिला संचालिकाओं के पास 14 वर्ष से लेकर 35-40 वर्ष तक की आयु की युवतियां संपर्क में होती हैं, जिन्हें ये रेट व ग्राहक के अनुसार बताए गए स्थान पर भेज देती हैं। इस व्यापार में दलालों की भी अहम भूमिका होती है। ये दलाल ही महिलाओं व ग्राहकों के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। जानकारी के अनुसार ये दलाल कॉलगर्ल युवतियों की फोटो की एल्बम व उनके संपर्क नंबर अपने पास रखते हैं और ग्राहकों की पसंद अनुसार मोटी राशि तय करके उन्हें उक्त स्थान का पता देकर भेज देते हैं। जानकारी के अनुसार महानगर के कुछ क्षेत्रों में इनके अड्डे बटाला रोड (अंदरूनी क्षेत्र), मजीठा रोड की कुछ स्लम बस्तियां, झब्बाल रोड, छेहर्टा के कुछ स्लम क्षेत्र, फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित नंगली, 88 फुट रोड के अलावा अन्य कुछ क्षेत्रों में भी यह धंधा फल-फूल रहा है। इसके अलावा पता चला है कि अब इस धंधे में कुछ हाई लेवल की महिलाएं भी संलिप्त हैं। शहर के विभिन्न होटल जैसे इस धंधे की शरणस्थली बन चुके हैं।

क्या कहना है पुलिस अधिकारी का

इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस बारे में पुलिस तेजी से कार्य कर रही है। पुलिस का साइबर सेल भी पैनी नजर बनाए हुए है। समय-समय पर देह व्यापार संबंधी कई लोगों व महिला संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना या जानकारी मिलती है तो तुरंत कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। इस दिशा में कुछ सफलताएं भी मिली हैं। अधिकारी ने कहा कि महानगर में इस प्रकार के अवैध धंधे को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस संबंध में कोई जानकारी है तो वह पुलिस से सांझा करे, उसका नाम व पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

उच्च वर्गीय लोग भी अवैध धंधे में संलिप्त

जानकारी मिली है कि इस मोटी कमाई वाले अवैध धंधे में कुछ उच्च वर्गीय लोग भी शामिल हैं, जो ज्यादातर बाहरी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ऐसे संचालक पॉश क्षेत्रों में किराए पर कोठी (बंगला टाइप) ढूंढकर इस धंधे को वहीं से चलाते हैं। ये पॉश क्षेत्र इसलिए चुनते हैं क्योंकि पुलिस की नजर अक्सर ऐसे इलाकों पर कम जाती है। पुलिस का शक कम होने का ये भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग अपना धंधा हाईटेक तरीके से अंदरखाते चलाते हैं। विगत समय पुलिस ने एक ऐसा ही रैकेट पकड़ा था, जो पॉश कॉलोनियों में रहकर ऐसे अवैध धंधे को अंजाम देता था। जब इस मामले की गहन जांच की गई तो यह काफी उच्च स्तरीय मामला निकला था। हालांकि अब यह धंधा होटलों में अंदरखाते धड़ल्ले से चलाया जा रहा है।

समय के साथ हाईटैक हो चुका है धंधा

हाईटैक युग के साथ-साथ अब यह धंधा भी समय के साथ हाईटैक हो चुका है। एंड्रॉयड फोन व सोशल मीडिया ने तो जैसे इस धंधे को काफी सरल बना दिया है। हाईटेक होने के कारण अब इस धंधे ने इंटरनेट के माध्यम से देश के हर राज्य में अपने पैर पसार लिए हैं। पूरी जानकारी उपलब्ध होने के चलते ग्राहकों को ढूंढने में अब कोई खास दिक्कत पेश नहीं आती। ग्राहक स्वयं इस प्रक्रिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आमतौर पर इस धंधे में ग्राहक को 1000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की राशि खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा कई शातिर लोग अपने नाम से साइट बनाकर ऐसी जानकारी इंटरनेट पर डालते हैं और ग्राहकों द्वारा संपर्क करने पर वे ही ग्राहकों से सारी बातचीत सेट करके कॉलगर्ल को बताए गए स्थान पर तय समय के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा विभिन्न पोर्न साइट्स ने भी इस चलन को बढ़ावा दिया है।

ए.एस.आई. की बेटी ने जीवित पिता का ही बनवा लिया डैथ सर्टीफिकेट

मोगा (सत्ता संदेश)-पंजाब पुलिस के ए.एस.आई.की बेटी ने सबको हैरान कर दिया है। पंजाब पुलिस के एक कर्मचारी की बेटी ने अपने जिंदा पिता को मरा हुआ बता दिया और उनका डैथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। हालांकि, यह धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और पुलिस ने अब उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लड़की ने कथित तौर पर इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए लोन लेने के लिए किया, जबकि उसे लोन नहीं मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोगा पुलिस ने लवप्रीत कौर के खिलाफ नकली डैथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके बैंक से पढ़ाई के लिए लोन लेने के आरोप में केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। लड़की के पिता पंजाब पुलिस में कर्मचारी हैं और मोगा के बाघापुराना में तैनात हैं। यह कार्रवाई एक शिकायत और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, 3 नवंबर 2025 को फरीदकोट के रहने वाले राजबिंदर सिंह भंगर द्वारा मोगा के एस.एस.पी. के पास शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मोगा के गांव दुनेके की रहने वाली लवप्रीत कौर, उसके पिता लखवीर सिंह, भाई मनप्रीत सिंह और मां गुरविंदर कौर ने लखवीर सिंह का नकली डैथ सर्टिफिकेट बनाकर बैंक और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को गुमराह किया। लवप्रीत कौर ने करीब 35 लाख रुपये के स्टडी लोन के लिए अप्लाई किया था। पुलिस जांच में पता चला कि लवप्रीत कौर ने विदेश (यूके) में पढ़ाई के लिए वीजा और लोन प्रक्रिया शुरू की थी। उसने पहले एक इमिग्रेशन एजेंसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए। बाद में, लोन प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट्स दूसरे एजेंट्स के जरिए भेजे गए। इसी प्रक्रिया के दौरान, कथित नकली डैथ सर्टिफिकेट भी जमा किया गया। जांच में यह भी पता चला कि लोन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई थी। लखवीर सिंह को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। दूसरी ओर, लवप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि कुड एजेंट्स ने उसकी जानकारी के बिना उसके डॉक्यूमैंट्स और फोटो का इस्तेमाल करके लोन के लिए अप्लाई किया और उसके पिता का डैथ सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिया। हालांकि, लवप्रीत अपने दावों के सपोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इसके आधार पर पुलिस ने लड़की के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस धोखाधड़ी में कोई और व्यक्ति भी शामिल है या नहीं।

धोखाधड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने लड़की के विरुद्ध किया केस दर्ज

पंजाब के दरियाओं से अवैध माइनिंग बन सकती है बरसातों में बाढ़ का बड़ा कारण

रोजाना निकाले जा रहे सैंकड़ों रेत के टिप्पर, सरकारी खजाने को लग रहा है चूना

अजनाला (सत्ता संदेश)-पिछले साल रावी दरिया में आई बाढ़ के पानी से अजनाला विधानसभा क्षेत्र के करीब 100 गांवों को नुकसान पहुंचा था और हजारों एकड़ धान, गन्ना और दूसरी खेती की फसलें बर्बाद कर दी थी। स्थानीय लोगों ने बाढ़ का कारण यह बताया था कि अजनाला हलके में रावी दरिया से कथित राजसी शह प्राप्त रेत माफिया द्वारा हजारों ट्रक रेत गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए थे, जिस कारण रावी दरिया का कुदरती बहाव गुम हो गया था और अवैध माइनिंग के कारण कमजोर हुए धुस्सी बांध को तोड़कर पानी गांवों में तबाही मचाने आ गया था। इस संबंध में भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि दरिया की डी-सिल्टिंग करने के नाम में विभाग द्वारा लगाए गए कैमरों को बंद करके कथित रेत माफिया द्वारा 200 के करीब गैर-कानूनी तरीके से रेत के लदे हुए टिप्पर घोनेवाल, कस्सोवाल और चाहड़पुर के पास दरिया से निकाले जा रहे हैं। इससे सरकारी खजाने को एक ही दिन में करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शक है कि इसमें पुलिस प्रशासन के कुछ आला अफसर और माइनिंग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रेत का पूरा प्रबंध कथित तौर पर राजसी शह प्राप्त लोगों द्वारा चलाया जा रहा हैं और आमतौर पर देखनो को मिला है कि गैर-कानूनी रेत के टिप्पर भरने वाले अड्डों और सियासी शह प्राप्त नुमाइंदें ही काबिज हैं। गांव वाले इन बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से गैर-कानूनी रेत माइनिंग जारी रही तो आने वाले बरसात के सीजन में फिर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।

कैप्टन को भाजपा में अपनी स्थिति और पंजाब को लेकर पार्टी की समझ पर उठाये सवाल की सजा मिली-परगट सिंह

कहा, सरकारें अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा रही हैं या उन्हें किनारे कर रही हैं

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समन भेजे जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा में अपनी स्थिति और पंजाब को लेकर पार्टी की समझ पर सवाल उठाए, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो गई। परगट सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती आ रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में विपक्षी नेताओं पर ईडी और अन्य एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब और किसानों के हित में खड़े हुए थे, तब भी कथित तौर पर उन्हें रोकने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया गया और उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब कैप्टन के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा किसी भी पंजाबी नेता के साथ हो सकता है। यह उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है, जो भाजपा या आम आदमी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। ऐसे नेताओं को कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है। परगट सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सेहत को लेकर चिंता जताई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने सलाह दी कि अब कैप्टन को अपनी सेवानिवृत्ति का जीवन शांतिपूर्वक बिताना चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी भाजपा के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार भी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कई मामलों में अपने ही विधायकों के खिलाफ एफ.आई.आई. दर्ज करवाई जाती है, जिससे मामले तार्किक नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा रही हैं या उन्हें किनारे कर रही हैं। परगट सिंह ने कहा कि पंजाब में मीडिया की आवाज दबाने के लिए भी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने दी हिमाचल वासियों को राहत

निजी भूमि पर सूखे खैर व बेकार पेड़ों की कर सकेंगे कटाई

शिमला (सत्ता संदेश)-हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य में निजी भूमि पर सूखे, गिरे हुए, फफूंद से प्रभावित और सड़े हुए खैर के पेड़ों को काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खैर के पेड़ पान में इस्तेमाल होने वाले 'कत्था' और उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड में कुछ हिस्सों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि पर्वतीय राज्य में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाले शीर्ष अदालत के 1996 के आदेश में 16 फरवरी, 2018 और 10 मई, 2023 को पहले ही संशोधन किया जा चुका है, जिससे खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति मिल गई है। इस मामले में अदालत मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले खैर के सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए जिला वन अधिकारी से संपर्क किया था और अनुमति न मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसके बाद याचिकाकर्त्ताओं ने निजी जमीनों पर ऐसे पेड़ों की कटाई के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 2018 में आदेश दिया था कि खैर के पेड़ों की कटाई सीधे वन विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा की जानी चाहिए, और कटाई का काम किसी भी निजी एजेंसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए, या ठेके पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया था कि वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेड़ों की कटाई वाले प्रत्येक क्षेत्र की वीडियोग्राफी नियमित अंतराल पर अलग से की जाए ताकि कटाई से पहले, कटाई के दौरान और कटाई के बाद जंगल की स्थिति और दशा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके।

राज्य ने अभी तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की

परमेश्वर ने कहा कि शीर्ष अदालत में इस तरह के पेड़ों को काटने के लिए याचिकाएं आमतौर पर सर्दियों के मौसम के बाद बड़ी संख्या में दायर की जाती हैं और न्यायालय ने पूर्व में राज्यों को इस तरह की मंजूरी देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश्वर सूद ने बताया कि राज्य ने अभी तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है और न ही उन्हें नियंत्रित करने वाले कोई नियम हैं। पीठ ने ऐसी समिति के गठन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 10 मई, 2023 के अपने पूर्व निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे पेड़ों की कटाई से संबंधित अनुमति को लेकर कार्रवाई की जा सके।

होली पर वैष्णो देवी कटड़ा से नई दिल्ली व बनारस के लिए स्पैशल ट्रेनों का संचालन

पठानकोट (सत्ता संदेश)-होली पर श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से नई दिल्ली विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04081/04082 और श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा से बनारस विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04603/04604 का संचालन किया जा रहा हैं। सूची के अनुसार, ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से कटड़ा 21 फरवरी से 8 मार्च तक 16 फेरों के साथ संचालित की जाएगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 11.45 बजे रवाना होकर अगले दिन 12 बजे कटड़ा पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से नई दिल्ली 22 फरवरी से 9 मार्च तक 16 फेरों के साथ संचालित की जाएगी, जो कटड़ा से रात में 09.20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा, ट्रेन संख्या 04603 वाराणसी से कटड़ा 24 फरवरी से 8 मार्च तक 4 फेरों के साथ संचालित की जाएगी।

पंजाब में 2-3 महीनों से बिजली बिल न जारी होने से खपतकार काफी परेशान

मानसा (सत्ता संदेश)-पावरकॉम की तरफ से पिछले 2 से 3 महीने से बिजली बिल जारी न करने की वजह से मानसा समेत पूरे पंजाब में खपतकार को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पंजाब सरकार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा दे रही है, इसके बावजूद लोग अपने बिजली बिलों को लेकर परेशान हैं। यह स्थिति खासकर उन घरों और कमर्शियल जगहों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है, जहां बिजली की खपत ज्यादा है। खपतकारों का कहना है कि समय पर बिजली बिल न मिलने की वजह से वे अपनी खपत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। कई लोग सरकारी हिदायतों के मुताबिक 2 महीने तक बिजली बचाकर 300 यूनिट की लिमिट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तीसरे महीने किसी वजह से खपत बढ़ जाती है तो उन्हें 3 महीने की कुल रीडिंग के आधार पर पूरा बिल देना पड़ सकता है। इससे वे मुफ्त बिजली की सुविधा से भी वंचित रह सकते हैं, जो उनके लिए बड़ा नुकसान है। शहर के कई व्यापारियों और दुकानदारों ने बताया कि कमर्शियल जगहों पर पहले से ही बिजली की खपत ज्यादा है। अगर बिल समय पर नहीं आते और बिल एक साथ आ जाते हैं, तो एक साथ बड़ी रकम देना मुश्किल हो जाता है। कुछ व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिल देर से आने पर पेनल्टी या सरचार्ज लगने का खतरा रहता है, जिसकी जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर ही थोंपी जाती है। कई लोगों को डर है कि जब कई महीनों की रीडिंग एक साथ की जाएगी, तो बिल अचानक बहुत बड़ी रकम का आ सकता है। इससे घर का बजट बिगड़ सकता है। यह स्थिति गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए और भी परेशानी वाली साबित हो सकती है। कुछ खपतकारों ने यह भी मांग की है कि अगर पावरकॉम की तरफ से बिल देर से जारी किए जाते हैं, तो खपतकारों पर कोई पेनल्टी या सरचार्ज न लगाया जाए और मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखी जाए। उनका कहना है कि जब गलती डिपार्टमेंट की है, तो इसका नुकसान आम लोगों को क्यों उठाना पड़े। खपतकारों ने मांग की है कि पंजाब सरकार और पावरकॉम मैनेजमेंट इस मामले पर पूरा ध्यान दें।

क्या कहा, पावरकॉम अधिकारी ने

जब इस बारे में पावरकॉम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो वे खुलकर कुछ भी कहने से परहेज करते रहे। हालांकि, कुछ अधिकारियों ने अनऑफिशियली माना कि यह समस्या सिर्फ मानसा जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब में है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में तकनीकी खराबी और हाल ही में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिलिंग प्रोसेस पर असर पड़ा है। इस कारण बिजली बिल जारी करने में देरी हो रही है। उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि अगर बिजली की रीडिंग समय पर नहीं हुई, तो उन्हें भविष्य में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

फगवाड़ा में बिक्रम मजीठिया ने कहा, भगवंत मान सरकार मेरी आवाज नहीं दबा सकती

फगवाड़ा (सत्ता संदेश)-शिरोमणि अकाली दल (ब) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया माननीय अदालत से जमानत मिलने के बाद श्री दरबार साहिब अमृतसर में नतमस्तक होने जाते समय फगवाड़ा बाईपास रोड पर पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। शिरोमणि अकाली दल विधानसभा हलका फगवाड़ा शहरी इंचार्ज रणजीत सिंह खुराना और ग्रामीण हलका इंचार्ज राजिंदर सिंह चंदी की अगुवाई में समूचे अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बोले सो निहाल और शिरोमणि अकाली दल जिंदाबाद के गगनभेदी जयकारे और नारे लगाते हुए फूलों के हार पहनाकर मजीठिया का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में जिला प्रधान (शहरी) जरनैल सिंह वाहद विशेष रूप से मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिक्रम मजीठिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्त्ताओं की दुआओं व परमात्मा की मेहर से उन्हें जमानत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के इशारों पर काम कर रही पुलिस और जेल प्रशासन ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि परिवार से मिलने से भी रोका गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जनता को यह कहकर गुमराह किया कि मुझे नशे के केस में गिरफ्तार किया गया है जबकि एफ.आई.आर. में किसी भी नशे का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि आय से अधिक संपत्ति का झूठा मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान सरकार चाहे जितने भी झूठे केस दर्ज कर ले, वह उनकी आवाज को दबा नहीं सकेगी। न वह कभी सरकार के आगे झुके हैं और न ही झुकेंगे। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने हमेशा हक और सच की बात की है और करता रहेगा।

शिअद 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर 'पंजाब बचाओ' अभियान करेगा शुरू-डा. चीमा

कहा, 17 फरवरी को कादियां से शुरू करके 13 अप्रैल तक 40 रैलियां करेगा शिरोमणि अकाली दल

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-शिरोमणि अकाली दल ने 2027 विधानसभा चुनावों के लिए 'पंजाब बचाओ-स. सुखबीर सिंह बादल लाओ' जनसंपर्क कार्यक्रम की घोषणा की। यह अभियान 17 फरवरी को कादियां से शुरू होकर 13 अप्रैल को बैसाखी पर समाप्त होगा पार्टी 40 रैलियां आयोजित करेगी, जिसमें 28 रैलियां 31 मार्च तक होंगी। सुखबीर बादल ने कहा कि सभी ज्वलंत मुद्दों पर दृष्टिकोण पेश किया जाएगा। डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि शेष 12 रैलियां अप्रैल में होंगी। चीमा ने बताया कि अकाली दल ने हमेशा नैतिक राजनीति की है। हमने अतीत में जो भी वायदा किया, उसे पूरा किया है। इस बार भी हम राज्य के लिए अपना दृष्टिकोण पेश करेंगे जो शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समाज के हर वर्ग को शामिल करेगा। इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा- वरिष्ठ अकाली नेता ने कहा कि पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करेगी और उनका समाधान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगी। इनमें पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को राज्य में हस्तांतरित करना और नदी

जल के संबंध में पंजाब के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना शामिल है। डा. चीमा ने कहा कि खेती संकट और किसानों द्वारा सामना की जा रही गंभीर मुद्दों के साथ साथ 2025 की बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलना, कर्जा और आत्महत्याएं शामिल हैं इन मुद्दों को रैलियों में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एम.एस.पी. को कानूनी गारंटी बनाना, उर्वरक सबसिडी में कमी करना और अमरीका के साथ व्यापार समझौते में किसानों के हितों की रक्षा करना जैसे मुद्दों को जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उठाया जाएगा। अनुसूचित जाति समुदाय की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी और ड्रग माफिया को संरक्षण देने के मुद्दों को भी मजबूती से उठाया जाएगा। अकाली नेता ने कहा कि पार्टी पंथक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा विशेष रूप से सिख धार्मिक संस्थानों को कमजोर करने के लिए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा, %हम इस साजिश में शामिल लोगों का पर्दाफाश करेंगे और पूरे पंथ से अकाली दल का समर्थन करने की अपील करेंगे, जो हमेशा सिखों के गौरव और प्रतिष्ठा के लिए सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा रहा है।'

पंजाब-हरियाणा व राजस्थान की जनता के लिए खुशखबरी

बठिंडा एम्स में 60 करोड़ रुपए से कैंसर को जांचने वाली हाईटेक मशीनें आईं

बठिंडा (सत्ता संदेश)-कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। फरवरी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) बठिंडा में अत्याधुनिक रेडियोथैरेपी और कैंसर जांच की सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। एम्स को कैंसर की जांच और उपचार के लिए 2 हाई एंड मशीनें मिली हैं, जिनमें हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर विद 3डी इमेजिंग और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन मशीन शामिल हैं। दोनों हाईटेक मशीनों की लागत 60 करोड़ है, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। अब मरीजों को कैंसर इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। एम्स

बठिंडा के एम.एस. डॉ. राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर एक अत्याधुनिक रेडियोथैरेपी मशीन है, जो इलेक्ट्रॉन को लगभग प्रकाश की गति तक पहुंचाकर उच्च ऊर्जा वाले एक्स-रे या इलेक्ट्रॉन बीम तैयार करती है। हाईटेक मशीनों से कैंसर कोशिकाओं को सटीक तरीके से नष्ट किया जा सकेगा। इससे आसपास के स्वस्थ उतकों को न्यूनतम नुकसान होता है। वहीं, पेट स्कैन एक नॉन-इनवेसिव न्यूक्लियर इमेजिंग तकनीक है, जिसका उपयोग कैंसर की पहचान, उसकी स्टेज तय करने और इलाज के दौरान निगरानी के लिए किया जाता है। ये दोनों अत्याधुनिक सुविधाएं अगले महीने से मरीजों के लिए शुरू कर दी जाएंगी। उम्मीद है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इन मशीनों का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से एम्स बठिंडा की स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार गोयल ने बताया कि निजी अस्पतालों में 3डी इमेजिंग से इलाज की लागत 4 लाख तक होती है, जबकि एम्स बठिंडा में यह सुविधा बहुत कम में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अत्याधुनिक कैंसर उपचार का लाभ मिलेगा। इन मशीनों के शुरू होने से न केवल बठिंडा, बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कैंसर मरीजों को सुलभ और सस्ता ईलाज मिल सकेगा।

पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रेगुलर करने के दिए आदेश

चंडीगढ़ - पंजाब में सालों से आउटसोर्स बेसिस पर काम कर रहे चौकीदारों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें रेगुलर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि लंबे समय से लगातार सर्विस के बावजूद कर्मचारियों को अस्थायी दर्जे पर रखना अनुचित लेबर प्रथा है और यह संविधान के बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने मनक सिंह और अन्य समेत कई पटीशनों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 15 अक्टूबर, 2020 के ऑर्डर के जरिए कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग को खारिज करना कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है।

भारत में डिजिटल क्रांति के साथ-साथ ऑनलाइन लूट का नया व खतरनाक दौर शुरू

31 अक्तूबर, 2025 तक 11 लाख फर्जी सिम कार्ड व 3 लाख मोबाइल फोन किए बंद

रामपुरा फूल (सत्ता संदेश)-भारत में डिजिटल क्रांति के साथ-साथ ऑनलाइन लूट का भी एक नया व खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 तक भारतीय लोगों का 52,976 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रत्येक वर्ष साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2024 में 22.68 लाख, 2023 में 15.56 लाख, 2022 में 9.66 लाख, 2021 में 4.52 लाख व 2020 में 2.57 लाख मामले रिपोर्ट किए गए। उधर, ग्रह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में दर्शाए गए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में जहां वर्ष 2021 में कुल 52,974 केस दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 65,893 हो गई और वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 86,420 तक पहुंच गया। हालांकि पंजाब में मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है जहां वर्ष 2022 में 697 मामले दर्ज हुए थे, जोकि 2023 में घटकर 511 रह गए, परंतु हरियाणा में 2021 में 622 केस थे, जोकि 2023 में बढ़कर 751 हो गए। इस तरह हिमाचल प्रदेश में जहां 2023 में 127 मामले दर्ज किए गए और राजधानी चंडीगढ़ में 2023 के दौरान 23 मामले दर्ज हुए। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 'भारतीय साइबर अपराध तालमेल केन्द्र' द्वारा कई कड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अधिक की राशि ठगों से जाने से रोकी गई। बैंकों के सहयोग से 10 सितम्बर, 2024 को एक 'संदिग्ध रजिस्ट्री' भी शुरू की गई थी, जिसके द्वारा 8,031 करोड़ रुपए की गलत ट्रांजैक्शनों को रोकने में

सरकार ने 31 अक्तूबर 2025 तक 11 लाख 14 हज़ार से अधिक फर्जी सिम कार्ड और 2 लाख 96 हज़ार मोबाइल हैंडसैट (आई. एम. ई. आई) ब्लॉक किए हैं। इसके अलावा आम जनता की सहायता के लिए शुरू की गई हैल्पलाइन 1930 व वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा लोगों की खून-पसीने की कमाई बचाई गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 अक्तूबर, 2025 तक 23 लाख से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 7,130 करोड़ रुपये से सफलता मिली। साइबर अपराधियों को पकडऩे के लिए 'प्रतिबिंब' नामक मॉड्यूल अपराधियों की लोकेशन को नक्शे पर ढूंढने में सहायता करता है और इस तकनीक की सहायता से अब तक 16,840 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी 2025 को 'साइबर मल्टी एजैंसी सैंटर' बनाया गया है जो साइबर जासूसी व उभर रही तकनीकों का दुरुपयोग जैसे बड़े खतरों से निपटेगा।

2027 में सत्ता में आने पर अकाली दल नशे और गैंगस्टरों का करेगा खात्मा-सुखबीर सिंह बादल

फिरोजपुर (सत्ता संदेश)-रा'यपाल गुलाब चंद कटारिया की ओर से फिरोजपुर में निकाली गई नशा विरोधी पदयात्रा में शामिल होने के लिए शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर पहुंचे और गवर्नर की पदयात्रा का हिस्सा बने। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वर्ष 2027 में अकाली दल की सरकार बनने के बाद पंजाब से ड्रग्ज की तस्करी और गैंगस्टरों के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुखबीर बादल ने इसके सथ ही पंजाब को नशा मुक्त बनाने के अभियान की अगुवाई करने के लिए गर्वनर गुलाब चंद कटारिया द्वारा की गई पहल की जमकर तारीफ की और सराहना की। रा'यपाल द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि रा'यपाल ने जनता की नब्ज समझ ली है इसीलिए उन्होंने इस बुराई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रा'य में ड्रग्ज अभिशाप बन गए हैं और पूरी पंजाब के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद सराहनीय हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की समस्या से निपटने में नाकामी के बावजूद रा'यपाल ने इस अभियान की अगुवाई करने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं रा'यपाल को सभी पार्टियों, सामाजिक संगठनों और शिक्षण संस्थाओं के नेताओं को इस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

80 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार लाहौर कॉलेज गुरुद्वारे में हुई अरदास

वर्ष 1947 के बाद से सिख विद्यार्थियों की कमी के कारण एचिसन कॉलेज बंद था

लाहौर (सत्ता संदेश)-पाकिस्तान के एचिसन कॉलेज परिसर स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में लगभग 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित की गई। कॉलेज के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वर्ष 1947 के बाद से सिख विद्यार्थियों की कमी के कारण एचिसन कॉलेज बंद था, हालांकि उसका रख-रखाव कॉलेज द्वारा किया जाता रहा। कॉलेज के मानद दूत डॉ. तरूणजीत सिंह बुटालिया ने बताया, 'लाहौर के मॉल रोड स्थित ऐचिसन कॉलेज परिसर के गुरुद्वारे में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक सिख अरदास सभा आयोजित की गई।' उन्होंने कहा कि यह विशेष आयोजन कॉलेज की 140वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें करीब 100 लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए भावुक क्षण था। मेरे पिता, दादा और परदादा विभाजन से पहले जब ऐचिसन कॉलेज में छात्र थे, तब वे प्रतिदिन शाम को यहीं अरदास देते थे।' उन्होंने बताया कि 140वीं

वर्षगांठ समारोह के लिए इस कार्यक्रम के आयोजन में उन्होंने सहयोग किया। कॉलेज के प्राचार्य हुसैन ने कहा, 'वर्ष 1947 के बाद ऐचिसन कॉलेज के गुरुद्वारे में आयोजित यह अरदास सेवा हमारी 140वीं वर्षगांठ की आध्यात्मिक शुरुआत है। हम भविष्य में ऐसे और अवसरों की उम्मीद करते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा दें।' एचिसन कॉलेज की आधारशिला 3 नवंबर 1886 को अविभाजित पंजाब के शाही और प्रमुख परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रखी गई थी।

सनी दयोल की 'लाहौर 1947' 13 अगस्त को होगी रिलीज

आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी अपकमिंग पीरियड ड्रामा 'लाहौर 1947' की थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पहली बार सनी दयोल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर आमिर खान एक साथ नजर आएंगे। आमिर खान ने कहा कि यह धरमजी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और मुझे बेहद खुशी होती अगर वह यह फिल्म देख पाते। बता दें कि 'लाहौर 1947' में सनी, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण दयोल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। निर्देशक राजकुमार और सनी की जोड़ी पहले भी 'घायल', 'घातक', और 'दामिनी' जैसी यादगार फिल्में दे चुकी है। अब कई सालों के बाद यह जोड़ी फिर से साथ लौट रही है जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। 1947 के दौर को जीवंत करने वाली यह फिल्म देशभक्ति और वीरता की एक नई मिसाल पेश कर सकती है।

अभिनेत्री उर्मिला मतोंडकर ने किया अपने प्रशंसकों का शुक्रिया

1990 के दशक की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मतोंडकर ने हाल ही में अपना जन्म दिन मनाया। इस मौके पर उसने अपने फैंस और चाहने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की। इसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उर्मिला ने पोस्ट कर लिखा, आज मेरा दिल आप सभी से मिले प्यार और आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ है। आप सभी ने मुझे बिना शर्त के जो प्यार दिया है, वही मेरी दुनिया है और मैं उसे आप सभी के साथ वापस बांटती हूं। उसने आगे लिखा, जिंदगी ऐसे अनगिनत छोटे-छोटे पलों से बनी होनी चाहिए, जिनमें हम 'यादा से 'यादा लोगों के चेहरे पर एक छोटी-सी मुस्कान ला सकें। भगवान की कृपा से मुझे ऐसे कई खूबसूरत पल मिले हैं। मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आगे भी मुझे ऐसे मौके मिलते रहें, जिनसे मैं किसी न किसी तरह दूसरों के जीवन में अच्छा बदलाव ला सकूं। उर्मिला ने आखिर में फैंस की तरफ से मिले समर्थन, अच्छाई और सराहना के लिए दिल से धन्यवाद किया। गौरतलब है कि उर्मिला ने सिनेमा जगत में 1990 के दशक में कदम रखकर धमाल मचाया था। वैसे उसने कैरियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी और सबसे पहले साल 1981 की फिल्म 'कलयुग' से सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन असल पहचान साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म 'मासूम' से मिली थी। इसके बाद आगे जाकर उसने बतौर लीड एक्ट्रैस भी काम किया और काफी नाम कमाया। फिल्म 'रंगीला' में काम करके वह रातोंरात स्टार बन गई थी। इसका गाना 'रंगीला रे' आज भी लोगों की जुबान पर है।

हरी घास पर चहलकदमी के लाभ

सुबह की ताज़ी हवा, ओस से भीगी हरी घास और शांत वातावरण–यह अनुभव केवल मन को ही नहीं, शरीर को भी सुकून देता है। वर्षों से यह माना जाता रहा है कि हरी घास पर नंगे पांव चलना आंखों की रोशनी बढ़ाता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह धारणा पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन हरी घास पर चहलकदमी के कई ऐसे लाभ हैं जो समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

रक्त संचार में सुधार- घास की मुलायम और असमान सतह पर चलने से पैरों के तलवों में हल्का दबाव बनता है। एक्यूप्रेशर सिद्धांतों के अनुसार तलवों में मौजूद कई बिंदु शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। इन बिंदुओं पर दबाव पड़ने से रक्त संचार बेहतर हो सकता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है।

एकाग्रता और सुकून में कमी- जमीन के सीधे संपर्क में आने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है। इससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो सकता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आंखों पर सीधा प्रभाव न डालते हुए भी शरीर को आराम मिलता है।

मानसिक तनाव में कमी- प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने से मन अपने आप शांत होता है। हरी घास पर नंगे पांव चलने से शरीर को प्राकृतिक संतुलन मिलता है, जो तनाव कम करने में मदद करता है। तनाव कम होने से आंखों पर पड़ने वाला दबाव भी अप्रत्यक्ष रूप से घट सकता है।

आंखों के अप्रत्यक्ष लाभ- हालांकि घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी सुबह की खुली हवा और हरियाली आंखों के लिए सुखद अनुभव प्रदान करती है। इससे डिजिटल आई स्ट्रेन से राहत मिल सकती है।

विटामिन-डी और ताज़ा ऑक्सीजन- सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन-डी के निर्माण में मदद करती है। हरी घास पर चलना और ताज़ी हवा में सांस लेना फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर को ताजगी महसूस कराता है।

कलाकार अपनी कला के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ सकते हैं-श्वेता त्रिपाठी

अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी सिर्फ अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन ही नहीं करतीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक और प्रेरित भी करना चाहती हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर श्वेता कहती हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूं, ताकि मुझे देखकर दूसरे भी प्रेरित हों। मेरे लिए वोट करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। लोग वोट करने नहीं जाते फिर कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं। दूसरा आज सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण भी है, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग सबसे 'यादा घातक है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। मैं इसलिए इन चीजों के बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि कलाकार लोकप्रिय होते हैं, तो जो भी वह करते हैं, उसका असर व्यापक होता है, इसलिए कलाकार की जिम्मेदारी समाज में आम नागरिक से 'यादा होती है। हमारा दायित्व है कि हम संविधान में निहित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में लोगों को आगे बढऩे के लिए प्रेरित करें। हमारा देश विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण है और कलाकार अपनी कला के माध्यम से इस विविधता की सुंदरता को दर्शाते हुए पूरे समाज को जोड़ सकते हैं।

बॉलीवुड की 90 प्रतिशत शादियां दिखावटी : प्रिया बनर्जी

सान्या सागर से 2023 में तलाक के बाद गत वर्ष प्रिया बनर्जी के साथ दूसरी बार विवाह बंधन में बंधे प्रतीक बब्बर ने शादी में पिता राज बब्बर सहित परिवार को नहीं बुलाया तो वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया था। प्रिया से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसने कहा, 'मैं ट्रोलर्स की परवाह नहीं करती।' खुद को कनाडाई मानने वाली प्रिया ने कहा, 'बॉलीवुड में 90 प्रतिशत शादियां दिखावटी होती हैं और मैं यह जानती हूं, क्योंकि मैंने इसे करीब से देखा है।' प्रतीक ने सहमति जताते हुए ट्विंकल खन्ना के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उसने अपने टॉक शो में फिजिकल चीटिंग के बारे में बात करते हुए कहा था, अगर शादीशुदा लोग 'रात गई बात गई' कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। प्रिया ने कहा, 'जब पुराने जमाने के एक्टर ऐसी बातें कहते हैं तो एक कनाडाई होने के नाते मैं यही कहूंगी कि यहां तो लोग शादी को मजाक समझते हैं। इमेज के लिए शादी मत करो।' प्रिया के राग में राग अलापते हुए प्रतीक ने कहा, 'मुझे लगता है कि धोखा देना, बेवफाई करना, एक से अधिक पार्टनर रखना, ये सब फैशन हो गया है। ये अच्छा नहीं है। पत्नी और गर्लफ्रैंड एक साथ रखना अच्छा नहीं है।' प्रतीक और प्रिया से पूछा गया कि जब उन्होंने राज बब्बर को शादी में आमंत्रित न करने का फैसला किया तो लोगों ने उन पर किस तरह हमला किया तो प्रतीक ने कहा, 'लोगों को सच्चाई नहीं पता। इंडस्ट्री के कुछ लोग सच्चाई जानते हैं, आम जनता कुछ नहीं लेकिन एक दिन, सबको सच्चाई पता चल जाएगी। किसी कहानी में या किसी किताब में या किसी इंटरव्यू में या किसी फिल्म में।' वहीं प्रिया ने कहा, 'इस अनुभव ने हमें एक टीम के तौर पर और मजबूत बनाया।

9वीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र अपनी 35 वर्षीय सगी चाची के साथ घर छोड़कर फरार

घटना के बाद रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक ढांचे को लेकर इलाके में बहस छिड़ गई

गोरखपुर (सत्ता संदेश)-उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 9वीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र अपनी 35 वर्षीय सगी चाची के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। दोनों करीब 10 दिनों तक लापता रहे और शादी की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते ट्रेस कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग हैरान हैं कि कैसे एक नाबालिग और उसकी चाची के बीच ऐसा रिश्ता पनप गया। जानकारी के मुताबिक, छात्र अपने माता-पिता, चाचा-चाची और अन्य परिजनों के साथ एक ही घर में रहता था। चाचा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, जिससे घर में चाची और भतीजे का साथ ज्यादा रहने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। परिवार के करीबी रिश्ते की वजह से किसी को शक नहीं हुआ और दोनों सामान्य रूप से एक-दूसरे से बात करते रहे। गत 26 जनवरी 2026 को छात्र और उसकी चाची अचानक घर से लापता हो गए। परिजनों ने पहले अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पीपीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सर्विलांस, सी.सी. टीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के जरिए दोनों की तलाश तेज कर दी। इसी बीच दूसरे थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान नाबालिग छात्र ने बताया कि वे दोनों शादी करने की योजना बना रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पीपीगंज थाने भेज दिया। थाने में परिजन पहुंचे, जहां करीब एक घंटे तक पंचायत चली। परिवार ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया और दोनों को अपने साथ घर ले गया। परिजनों ने बातचीत और समझाइश के जरिए छात्र और महिला को इस फैसले से पीछे हटने के लिए राजी किया। चाचा ने भी भतीजे के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन परिवार की सामूहिक सलाह के बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने इसे संवेदनशील पारिवारिक मामला मानते हुए आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना के बाद गोरखपुर में रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक ढांचे को लेकर गहरी बहस छेड़ रही है। लोग यह समझने में असमर्थ हैं कि कैसे एक नाबालिग छात्र और उसकी चाची के बीच इतना गहरा संबंध बन गया कि वे घर छोडने तक को तैयार हो गए।

हिमाचल में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला जगजाहिर

हि.प्र. (सत्ता संदेश)-हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला पुलिस थाना हमीरपुर ने झारखंड से बच्चों को लाकर बाल मजदूरी करवाने वाले एक गिरोह की सक्रियता पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में दुलारी देवी नामक एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड की रहने वाली है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब चाइल्ड वैलफेयर कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) को हेल्पलाइन नंबर के जरिए शिकायत मिली। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए छापेमारी की और दो नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचाया। चौंकाने वाली बात यह है कि रैस्क्यू किए गए बच्चों में से एक को हमीरपुर और दूसरे को कुल्लू से बरामद किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी महिला दुलारी देवी, हिमाचल के ही एक व्यक्ति के कहने पर झारखंड से 5 नाबालिग बच्चों को यहां लाई थी। आशंका जताई जा रही है कि इन बच्चों को अलग-अलग जिलों में बाल श्रम के लिए बेचा या भेजा गया था। पुलिस अब इस मामले में वित्तीय लेन-देन और तस्करी के इस नैटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। एस.पी. बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मानव तस्करी और बाल श्रम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी महिला से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाकी बच्चे कहां हैं और इस घिनौने व्यापार में और कौन-कौन से चेहरे शामिल हैं।

हमीरपुर पुलिस की रेड में हुआ अहम खुलासा

'सेवा तीर्थ' भवन के नामकरण का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन

नेशनल डेस्क (सत्ता संदेश)-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेवा तीर्थ' भवन परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय अब नए परिसर में कार्य करेगा। दोपहर लगभग 1.30 बजे प्रधानमंत्री ने 'सेवा तीर्थ' नाम का अनावरण किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नए परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके साथ ही देश का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र अब %सेवा तीर्थ' से संचालित होगा। दारा शिकोह रोड स्थित 'सेवा तीर्थ' परिसर लगभग 2.26 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस अत्याधुनिक परियोजना पर करीब 1,189 करोड़ की लागत अनुमानित है। यह नया प्रशासनिक परिसर अलग-अलग स्थानों पर संचालित होने वाले प्रमुख सरकारी दफ्तरों को एक ही छत के नीचे लाने की सोच के साथ तैयार किया गया है, ताकि समन्वय बेहतर हो और कामकाज में तेजी आए। 'सेवा तीर्थ' में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को एकीकृत रूप से स्थापित किया गया है। सरकार का कहना है कि वर्ष 2014 के बाद से प्रशासनिक ढांचे और सरकारी परिसरों के नामों में बदलाव की पहल औपनिवेशिक विरासत से आगे बढ़कर भारतीय मूल्यों और जनभावनाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से की गई है। इसी क्रम में साउथ ब्लॉक का नाम बदलकर 'सेवा तीर्थ', सेंट्रल सचिवालय का 'कर्तव्य भवन', राजपथ का 'कर्तव्य पथ', रेस कोर्स रोड का 'लोक कल्याण मार्ग' और राज भवन/राज निवास का 'लोक भवन/लोक निवास' किया गया है।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 50वीं मीटिंग में भक्तों की सुविधा हेतु लिए कई फैसले

विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर भी चर्चा करके कल्याणकारी योजनाओं को दी मंजूरी

जम्मू (सत्ता संदेश)-जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 50वीं मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में इस वर्ष की तैयारियों और प्रबंधों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस वर्ष 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर प्रथम पूजा कराने का निर्णय लिया गया है, जबकि बाबा बर्फानी को समर्पित लेजर और साऊंड शो को मंजूरी दी गई है। श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर लेजर और साऊंड शो होस्ट किया जाएगा। यह शो एक कल्चरल लाइट हाऊस के तौर पर भी काम करेगा जो केंद्र शासित प्रदेश के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास को दिखाएगा। बोर्ड ने कहा कि यात्रा की औपचारिक शुरुआत की तारीख जल्द ही फाइनल की जाएगी। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बोर्ड ने 2026 यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक अनुभव और सुविधा को और बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रमुख उपायों को मंजूरी दी। श्राइन बोर्ड ने पंजीकृत यात्रियों, सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों, मौसमी श्रमिकों और पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का फैसला किया। उप-राज्यपाल ने श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर भी चर्चा की और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। इसके उपरांत उप-राज्यपाल ने अधिकारियों को यात्रा के मार्ग में उपयुक्त शौचालय सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने तीर्थयात्रियों, सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा कर्मियों के लिए पटरियों पर बारिश से बचाव के लिए शैड (आश्रयों) के निर्माण करने के निर्देश दिए। बैठक में चल रही परियोजनाओं, यात्रा संबंधी जानकारी का प्रसार, ट्टुओं के लिए बीमा कवर, मौसम का अनुमान लगाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम, सिक्योरिटी और निगरानी, सर्विस के लिए डिजिटल प्री-पेड सिस्टम, दोनों रास्तों पर कमजोर हिस्सों पर क्रैश बैरियर और सेफ्टी रेलिंग लगाने व अलग-अलग डिपार्टमैंट द्वारा किए जा रहे अलग-अलग कामों में हुई प्रोग्रैस पर चर्चा की गई।

बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते होंगे चौड़े

बैठक में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (बी.आर.ओ.) द्वारा यात्रा ट्रैक के मैंटीनैंस, रैस्टोरेशन और डिवैल्पमैंट का रिव्यू किया गया और बताया गया कि बी.आर.ओ. ने बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर आरामदायक ट्रैक को चौड़ा कर दिया है। इस काम में काफी प्रोग्रैस हुआ है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डा. मंदीप के. भंडारी ने आने वाली यात्रा के इंतजामों के बारे में एक प्रैजेंटेशन दिया। बैठक में श्राइन बोर्ड के कई सदस्य व यू.टी. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धर्मगुरु दलाईलामा 2 माह बाद लौटेंगे मैक्लोडगंज

धर्मशाला (सत्ता संदेश)-शीतकालीन दक्षिण भारत यात्रा के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा आज मैक्लोडगंज पहुंचेंगे। दलाईलामा आज सुबह करीब 9.88 बजे कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत को लेकर कांगड़ा एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक जगह-जगह तोरण द्वार सजाए जाते हैं। दलाईलामा की करीब 2 महीने के बाद वापसी हो रही है। तिब्बती नववर्ष लोसर से पहले दलाईलामा के आगमन को लेकर तिब्बती समुदाय में खासा उत्साह है। समुदाय के लोगों का कहना है कि दलाईलामा की मौजूदगी में लोसर का उल्लास दोगुना हो जाता है। दलाईलामा के मैक्लोडगंज प्रवास के दौरान देश-विदेश से बौद्ध अनुयायी और प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में चहल-पहल बढ़ जाती है। उनके आगमन से पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है, जिसे लेकर स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह है।

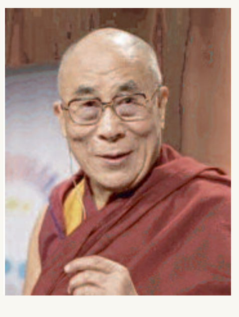

ट्रंप प्रशासन ने ताइवान पर टैरिफ घटाकर 15 प्रतिशत किया

वॉशिंगटन- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ताइवान के साथ एक व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के तहत ताइवान ने अपनी 99 प्रतिशत टैरिफ पाबंदियों को हटाने या कम करने पर सहमति जताई है। यह जानकारी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने दी। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए काफी हद तक ताइवान पर निर्भर है। साल 2025 के पहले 11 महीनों में चिप निर्यात के कारण दोनों देशों के बीच लगभग 127 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया था।

आधार के तकनीकी ढांचे में व्यापक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम

आधार विजन 2032-फिंगरप्रिंट की जगह अब चेहरे से पहचान की तैयारी

नई दिल्ली (सत्ता संदेश)-आधार के तकनीकी ढांचे में व्यापक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब चार महीने के मैराथन विचार-विमर्श के बाद गठित विशेषज्ञ समिति ने 'आधार विजन 2032' का दस्तावेज तैयार किया है। इसके प्रारूप को अगले महीने समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च में यू.आई.डी.ए.आई. को सौंपा जाएगा। इसी विजन के अनुरूप अगले पांच साल के लिए आधार का नया तकनीकी ढांचा तैयार होगा। सूत्रों के मुताबिक आधार विजन 2032 में ए.आई., क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। मकसद आधार को 'यादा सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाना है, ताकि फ्रॉड की आशंका कम हो। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकग्निशन को प्राथमिक माध्यम बनाया जाएगा। इससे तकनीकी फेलियर और ऑथेंटिकेशन में आने वाली असुविधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। यह दस्तावेज बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में यूआईडीएआई के चेयरमैन नीलकांत मिश्रा की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इसमें सर्वम् ए.आई. के सह-संस्थापक विवेक राघवन, न्यूटनिक्स के संस्थापक धीरज पांडेय, अमृता यूनिवर्सिटी के डॉ. पी. पूर्णचंद्रन, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रो. अनिल जैन व आईआईटी जोधपुर के मयंक वत्स थे। दूसरी तरफ आधार के सी.ई.ओ. भुवनेश कुमार ने कहा कि भले ही विजन 2032 का लक्ष्य है, लेकिन तैयारी उससे आगे की तकनीक को ध्यान में रखकर हो रही है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग से तकनीकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ऐसे में आधार के ढांचे को मजबूत बनाना जरूरी है। इसका मकसद अगले 10 साल तक आधार कार्ड का तकनीकी ढांचा विश्वस्तरीय बनाए रखना है, ताकि स्पीड, मेमोरी और साइबर सिक्योरिटी में भारत पीछे न रहे। यूआईडीएआई 473 नए आधार केंद्र खोलेगा, जबकि अभी सिर्फ 80 केंद्र हैं।

रोज 9 करोड़ आधार ऑर्थोटिकेशन होते हैं

रोज करीब 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन। इनमें लगभग 1 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए होते हैं। सरकार का लक्ष्य हर महीने 100 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन फेशियल रिकग्निशन से करने का है। ए.आई. के इस्तेमाल से फेशियल रिकग्निशन सिस्टम समय-समय पर अपडेट हो सकेगा। बार-बार बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए अनुबंध से पहले सरकार 18 करोड़ बच्चों, किशोरों के बायोमेट्रिक अपडेट पर भी जोर दे रही है। दिसंबर तक करीब 5 करोड़ अपडेट हो चुके हैं। यह प्रक्रिया सितंबर 2026 तक, निश्शुल्क जारी रहेगी। यू.आई.डी.ए.आई. के साथ सरकार का मौजूदा अनुबंध 2027 में खत्म होगा । 2032 तक के लिए नया अनुबंध करने की तैयारी है।

दुनिया भर में ऐतिहासिक जेलें आलीशान पंचतारा और बुटीक होटलों में तबदील

नई दिल्ली (सत्ता संदेश)-कभी कठोर अनुशासन, संकरी कोठरियों और साधारण भोजन के लिए जानी जाने वाली जेलें अब दुनिया के कई हिस्सों में विलासिता, आराम और विरासत पर्यटन की मिसाल बनती जा रही हैं। विरासत इमारतों के संरक्षण की इस प्रवृत्ति के तहत कई ऐतिहासिक जेलों को पंचतारा और बुटीक होटलों में बदला जा रहा है। इस कड़ी में जापान के नारा शहर की पूर्व किशोर जेल नया आकर्षण बनने जा रही है। मेइजी काल में 1908 में स्थापित यह जेल 2017 तक कार्यरत रही और बाद में इसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपत्ति घोषित किया गया। अब एक प्रतिष्ठित जापानी होटल ब्रांड इसे जून 2026 में ऑल-सूट होटल के रूप में खोलने जा रहा है। प्रत्येक सुइट के लिए 9 से 11 पुरानी कोठरियों को जोड़ा गया है। पूर्व निरोध विभाग में जापानी-फ्रेंच रेस्तरां होगा और परिसर में नारा प्रिजन म्यूजियम भी खुलेगा। नारा जेल ऐसा पहला उदाहरण नहीं है। तुर्किये के इस्तांबुल स्थित सुल्तानाहमेत की पूर्व जेल आज फोर सीजन्स होटल है, जिसे 1918 में तुर्की नवशास्त्रीय शैली में बनाया गया था। जर्मनी के ऑफेनबुर्ग की ऐतिहासिक जेल 'होटल लिबर्टी' के रूप में पहचानी जाती है, जहां आज भी प्रतीकात्मक सेल दरवाजे लगाए गए हैं। अमरीका के बोस्टन की चार्ल्स स्ट्रीट जेल आज 'द लिबर्टी' होटल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की पेंट्रिज जेल में 'द इंटरल्यूड' नामक बुटीक होटल संचालित है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के रूपांतरण न केवल विरासत संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। जहां कभी कैद थी, वहां अब सुकून और विलासिता है।

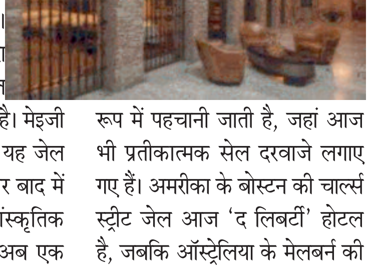

अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया

नई दिल्ली (सत्ता संदेश)-साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया है। शाह के अनुसार, साइबर फ्राड अब एक संगठित अपराध का रूप धारण कर चुका है। इससे सभी को मिलकर निपटना होगा। बड़ी संख्या सिम कार्ड, आई.एम.ई.आई. नंबर ब्लाक कराने से लेकर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई रकम को वापस कराने में मिल रही सफलता का हवाला देते हुए उन्होंने रा'यों को हेल्पलाइन नंबर 1930 के लिए पर्याप्त मात्रा में कालर बैठाने को कहा, ताकि समय पर कार्रवाई से फ्राड की रकम को तत्काल फ्रीज किया जा सके। साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने एक ओर तेजी से बढ़ते साइबर फ्राड के आंकड़े दिए तो वहीं उससे निपटने के लिए एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। शाह ने बताया कि 20 हजार करोड़ रुपये के साइबर फ्राड के मामले दर्ज किये गए हैं, जिनमें से 8,189 करोड़ रुपये फ्रीज करने या पीड़ित को वापस लौटाने में सफलता मिली है।

पूरी तरह से ई-बस में साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट वाला शहर बना अहमदाबाद

अहमदाबाद की सड़कों पर अब 'साइबर कवच' के साथ दौड़ेंगी 28 नई हाईटेक ई-बसें

अहमदाबाद को प्रदूषण-मुक्त और हरा-भरा बनाने की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम

अहमदाबाद (सत्ता संदेश)-गुजरात में अहमदाबाद ने सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा बदलते हुए देश की पहली 'साइबर सुरक्षित' बस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 28 अत्याधुनिक इलैक्ट्रिक ए.सी. बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें न केवल प्रदूषण मुक्त हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा और %फायर फाइटिंग' सिस्टम से लैस भारत की पहली बसें बन गई हैं। इसी के साथ अहमदाबाद ग्रीन मोबिलिटी और यात्री सुरक्षा के मामले में देश का अग्रणी शहर बन गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (ए.एम.टी.एस.)का लक्ष्य शहर को पूरी तरह से डीजल मुक्त बनाना है। इन बसों को चलाने के लिए टैंडर से लेकर डिलीवरी तक का काम मात्र 6 महीने में पूरा हुआ। मार्च 2026 तक सड़कों पर कुल 225 नई ई-बसें उतारने की योजना है। 225 ई-बसों के बेड़े से सालाना 75,000 किलो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस के बेड़े में 28 नई इलेक्ट्रिक ए.सी. बसों के लॉन्च के साथ, शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और भी मॉडर्न, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल हो गया है। इन बसों की सबसे बड़ी खासियत इनका स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। देश में पहली बार, पूरी तरह से ई-बस में साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट लागू किया गया है, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम जैसी एडवांस्ड फायर अलार्म सुविधाएं भी दी गई हैं। आने वाले साल में सभी ए.एम.टी.एस. बसों को इलेक्ट्रिक करने की योजना है। यह अहमदाबाद को प्रदूषण-मुक्त और हरा-भरा शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमरीका के कैलिफोर्निया में भारतीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 9 फरवरी से था लापता

वाशिंगटन- छह दिनों से लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया (22) अमेरिका के कैलिफोर्निया में मृत पाया गया है। श्रीनिवासैया बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में केमिकल और बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह नौ फरवरी से लापता था। बयान कहा गया है, 'परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए दूतावास तैयार है। इसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने की व्यवस्था शामिल है। हमारे अधिकारी परिवार के सीधे संपर्क में हैं और सभी आवश्यक औपचारिकताओं और सेवाओं में उनका सहयोग करेंगे।'

देशभर में बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय

नई दिल्ली (सत्ता संदेश)-देशभर में बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित राष्ट्रव्यापी नैटवर्क या रा'य-विशिष्ट सक्रिय गिरोह काम कर रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझना आवश्यक है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई खास पैटर्न है या ये महज छिटपुट घटनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सभी रा'यों से इस संबंध में डाटा एकत्र करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि कुछ रा'यों ने लापता बच्चों और अभियोजन से संबंधित डाटा सझझा किया है, लेकिन अभी भी लगभग एक दर्जन राज्यों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विश्लेषण तभी कर पाएगी, जब उसे सभी राज्यों से पूर्ण डाटा प्राप्त होगा। पीठ ने कहा, %हम जानना चाहते हैं कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या राज्य-विशिष्ट सक्रिय गिरोह है। क्या यह एक पैटर्न है या सिर्फ एक छिटपुट घटना?' कोर्ट ने उन राज्यों की आलोचना की जिन्होंने डाटा नहीं दिया है और चेतावनी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो सख्त आदेश पारित किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया, कि जो बच्चे रैसक्यू किए जा चुके हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाए ताकि यह पता चल सके कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है।

*** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पता लगाने का दिया निर्देश**

*** बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे अहम सवाल**

गोद लेने की जटिल प्रक्रिया और समन्वय की कमी

वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने इस दिशा में पहल की है और सभी राज्यों को डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह सुनवाई एनजीओ 'गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान' द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर हो रही थी, जिसमें बच्चों के लापता होने के अनसुलझे मामलों को उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'देश में गोद लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल और कठोर है कि लोग अक्सर अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय की भारी कमी है, जिसे ठीक करने की जरूरत है।

प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में रिकॉर्ड छठा विश्व खिताब जीता

मनामा में आयोजित BWF Para Badminton World Championships में भारत के स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने इतिहास रच दिया।

37 वर्षीय भगत ने पुरुष एकल एसएल3 वर्ग के फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद अल इमरान को 21-12, 21-18 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह उनके करियर का लगातार चौथा विश्व चैंपियनशिप एकल स्वर्ण और कुल मिलाकर छठा विश्व खिताब है।

एसएल3 वर्ग में वे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनके निचले अंगों में गंभीर विकलांगता होती है। पांच साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद भगत ने अपने खेल से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है।

उन्होंने इससे पहले 2009, 2015, 2019, 2022 और 2024 में भी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इस जीत के साथ वह विश्व चैंपियनशिप इतिहास में सबसे सफल एकल खिलाड़ी बन गए हैं। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में वे डोपिंग रोधी नियमों के 'वेयरअबाउट्स' उल्लंघन के कारण 18 महीने के निलंबन का सामना कर चुके थे, जिसकी वजह से वह 2024 पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए थे। लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया।

क्रिकेट के दो ऐसे खिलाड़ियों की कहानी, जिनका बचपन किसी और देश में बीता

दिग्गज ब्रेट ली जैसा बॉलिंग एक्शन करने वाले करन केसी

मुंबई (सत्ता संदेश)-नेपाल में जन्मे करन का बचपन चंडीगढ़ में बीता, जहां उनके पिता काम करते थे। वहां के क्रिकेट सर्किट में वे जाना-माना नाम थे। प्रोफैशनल क्रिकेट शुरू करने के बाद वे गर्मियों में ट्रेनिंग के लिए मुंबई आते थे। अक्सर चर्चगेट स्टेशन के बाहर खड़े होकर, वे वानखेड़े स्टेडियम को निहारते और वहां खेलने का सपना बुनते थे। 20-22 साल की उम्र में अनिश्चित भविष्य और पिता की इच्छा के कारण वे 2014 में नेपाल लौट गए ताकि नौकरी के लिए मलेशिया जा सकें। तब टीवी पर नेपाल को वर्ल्ड कप खेलते देख उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। कॉलेज टूर्नामेंट में किसी और के नाम से खेलते हुए उन्होंने तेज गेंदबाजी से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि सलेक्टर्स की नजरों में आ गए। 2015 में नेपाल के लिए डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली को आदर्श मानने वाले करन का गेंदबाजी एक्शन भी उन्हीं से प्रेरित है। वानखेड़े में खेलने का सपना पूरा करने के साथ-साथ, उनका एक निजी सपना माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का भी है।

कभी पिज्जा बनाने वाले क्रिशन कलुगामागे अब घुमा रहे हैं वर्ल्ड कप में गेंद

मुंबई (सत्ता संदेश)-इटली के मिस्ट्री स्पिनर क्रिशन कलुगामागे का जन्म श्रीलंका में हुआ था, लेकिन 15 की उम्र में वे परिवार के साथ इटली में बस गए। शुरुआत उन्होंने एथलेटिक्स से की। क्रिशन इटली के ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मार्सेल जैकब्स के साथ ट्रेनिंग करते थे और शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलते थे। लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए इटली के सबसे पुराने क्लबों में से एक 'रोमा क्रिकेट क्लब' ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। इटली में क्रिकेट खेलना और आजीविका चलाना बड़ी चुनौती थी। क्रिशन पिज्जा बनाने का काम करते थे, लेकिन क्रिकेट के जुनून ने उनसे कई नौकरियां छीन लीं। वे बताते हैं, 'रविवार को पिज्जा की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है और रविवार को ही हमारे मैच होते थे। इस वजह से मुझे कई बार काम से निकाला गया।' इटली के कोच जॉन डेविसन उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज मानते हैं। डेविसन वही कोच हैं, जिन्होंने नाथन लियोन जैसे महान स्पिनर को तराशा है। क्रिशन का मानना है कि चाहे पिज्जा बेस तैयार करना हो या लेग-स्पिन से गेंद को टर्न कराना, सब कुछ अंगुलियों का खेल है। वे इटली के उन 5 चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं, जो देश में रहकर प्रैक्टिस करते हैं।

विक्टोरिया म्बोको ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन रयबाकिना को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

दोहा - पिछले कुछ महीनों में विक्टोरिया म्बोको ने टॉप 15 में पहुंचने के दौरान कई मौकों पर चैंपियन वाली सोच दिखाई है। कनाडा की इस टीनेजर ने शुक्रवार को कतर टोटल एनर्जीज ओपन में इसे फिर से दिखाया, फाइनल सेट में ब्रेक डाउन से उबरकर दूसरी सीड और मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन एलेना रयबाकिना को क्वार्टरफाइनल में बाहर कर दिया।

म्बोको अभी नंबर 13 पर हैं, पिछले अगस्त में मॉन्ट्रियल में नेशनल बैंक ओपन में अपने सफल टाइटल रन के रास्ते में रयबाकिना को पहले ही हरा चुकी थीं। लेकिन यह वर्ल्ड नंबर 3 थीं जिन्होंने पिछले साल वाशिंगटन और टोक्यो में म्बोको को हराने के बाद अपने हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में 2-1 की बढ़त के साथ मैच में एंट्री की थी। उनकी नई दुश्मनी का चौथा चैप्टर तब शुरू हुआ जब म्बोको ने 2-0 की बढ़त बना ली, लेकिन रयबाकिना ने अगले छह में से पांच गेम जीतकर 5-3 की बढ़त बना ली। लेकिन कनाडाई खिलाड़ी ने फिर से मोमेंटम बदला, लगातार चार गेम जीतकर पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर लिया।

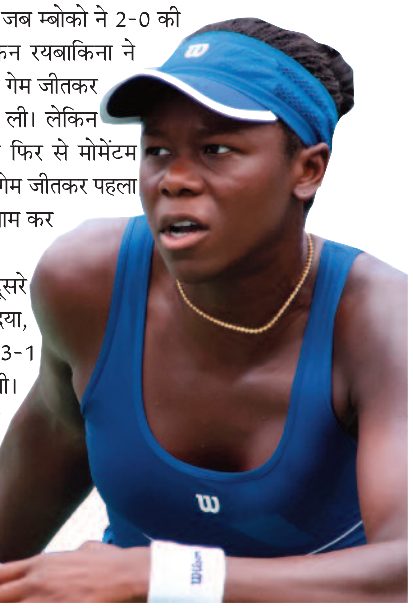

रयबाकिना ने दूसरे सेट में जवाब दिया, जल्दी ब्रेक करके 3-1 की बढ़त बना ली। म्बोको ने ब्रेक करके 3-3 से बराबरी कर ली, लेकिन कज़ाख खिलाड़ी ने सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।

वेस्टइंडीज टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक, सुपर-8 में पहुंचने वाली पहली टीम

नई दिल्ली- अनुभवी ऑलराउंडर जैसन होल्डर की धारदार गेंदबाजी और कप्तान शाई होप और फॉर्म में चल रहे शिमरॉन हेटमायर की आतिशी साझेदारी की बदौलत वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत हासिल की और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहे। वानखेड़ें में खेले गए मैच में नेपाल किसी भी वक्त मैच में वापस आता नजर नहीं आया और मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की शुरुआत बेहद खराब रही और वो 11 ओवर तक सिर्फ 46 रन बनाए और इस दौरान पांच विकेट गंवा दिए। बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए।

कजाकिस्तान के अलीशेर नें जीता छोला ग्रैंडमास्टर्स शतरंज

चेन्नई - भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंडमास्टर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुए प्रथम छोला शतरंज ग्रैंडमास्टर्स नॉर्म टूर्नामेंट का खिताब कजाकिस्तान के अलीशेर सुलेमेनोव नें अपने नाम कर लिया है । नौ राउंड के बाद अलीशेर 6 अंक बनाकर पहले स्थान पर रहे । आख़िरी राउंड में अलीशेर और औदी अमेय के बीच एक रोमांचक बाजी ड्रा रही और औदी अमेय 5.5 अंक बनाकर टाईब्रेक में तीसरे स्थान पर रहे हालांकि वह आधा अंक से ग्रैंडमास्टर नार्म से लेने से चूक गए । 5.5 अंकों पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर भारत के एथन वाज दूसरे स्थान पर रहे । क्यूबा के डेलगाड़ो रेमरीज़ 5 अंकों पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर चौथे स्थान पर रहे जबकि इतने ही अंकों पर मयंक चक्रवर्ती और आरोण्यक घोष पाँचवें और छठे स्थान पर रहे । अन्य खिलाड़ियों पर फ्रांस के माहेल बॉयर 3.5 अंक बनाकर सातवे , फ्रांस के जोसफ गिरेल 3 अंक बनाकर आठवें ,अक्षय बरगोंकर3 अंक बनाकर नौवे और हर्ष सुरेश 2.5 अंक बनाकर आख़िरी स्थान पर रहे ।

होटल में बुकिंग ना होने पर मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी खिलाड़ी, सड़क पर गुजारे कई घंटे

कराची - पाकिस्तान हॉकी टीम के सदस्यों को कैनबरा पहुंचने पर कई घंटे सड़क पर बिताने पड़े क्योंकि पैसों के अभाव में पाकिस्तान हॉकी महासंघ होटल के बिल का भुगतान नहीं कर सका जिससे होटल बुकिंग रद्द हो गई। पाकिस्तानी टीम होबर्ट में FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच खेलने आस्ट्रेलिया में है। टीम के सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को घंटों तक सड़क पर रहना पड़ा।

एक सूत्र ने बताया, 'खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए कैनबरा में एक चार सितारा होटल में कमरे बुक किए गए थे। उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान खेल बोर्ड और पीएचएफ ने कैनबरा में उनके रहने के लिए सारे भुगतान कर दिए हैं।' सूत्र ने कहा, 'लेकिन पिछले सप्ताह कैनबरा पहुंचने पर पता चला कि उस होटल में कोई बुकिंग थी ही नहीं। टीम के मुख्य कोच ताहिर जमान टाइम जोन अलग होने के कारण PSB और PHF अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सके।'

सूत्र ने कहा, 'ताहिर ने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया कि लाहौर से लंबा सफर करके आए खिलाड़ियों के पास आराम करने की कोई जगह नहीं है।'हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और टीम प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी शीर्ष टीमों से खेल रही है। सूत्र ने बताया कि कई घंटे बाहर इंतजार करने के बाद होटल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को कुछ कमरे दिए। सूत्र ने कहा, 'कमरे उपलब्ध नहीं थे लिहाजा एक ही कमरे में दो तीन खिलाड़ी रूके और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने स्टेडियम गए जिसमें 2-3 से पराजय मिली।'

इससे पहले अर्जेंटीना में प्रो लीग के पहले चरण में खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते नहीं मिले थे जिससे विदेश में उन्हें पैसों की किल्लत हो गई। कैनबरा में टीम मैनेजर के बिना गई है क्योंकि नियमित मैनेजर और पूर्व ओलंपियन अंजुम सईद को PHF ने निकाल दिया है। उन्हें वापिस लौटते समय फ्लाइट में सिगरेट पीते पाया गया और हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों से उनकी झड़प भी हुई।

इंग्लैंड के आदिल राशिद टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज़ बने

कोलकाता (पश्चिम बंगाल)- इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद रविवार को श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा को पीछे छोड़कर पुरुषों के टी20 क्रिकेट में पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 37 साल के राशिद ने ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ ग्रुप C ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान तीन विकेट (चार ओवर में 3/36) लेकर यह उपलब्धि हासिल की। हसरंगा, जो अब छठे स्थान पर हैं, ने सबसे छोटे फॉर्मेट में 95 मैचों और 93 पारियों में 154 विकेट लिए हैं। इस चालाक स्पिनर का बॉलिंग एवरेज 16.05 है, जिसमें टी20 में पांच बार चार विकेट शामिल हैं। राशिद ने टी20 में 140 मैचों और 133 पारियों में 155 विकेट लिए हैं। 37 साल के इस खिलाड़ी का बॉलिंग एवरेज 23.43 है, जिसमें चार चौके शामिल हैं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (158), न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी (162), पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउथी (164), और अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान (190) राशिद से आगे हैं। मैच की बात करें तो, टॉम बैंटन की शानदार हाफ सेंचुरी और स्पिनर आदिल राशिद के तीन विकेट हॉल की वजह से इंग्लैंड ने शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ICC टी20 वर्ल्ड कप के मैच में स्कॉटलैंड को पांच विकेट से हरा दिया, जिससे टूर्नामेंट में यूरोपियन देशों के खिलाफ उनकी टीम का बिना जीत का सिलसिला खत्म हो गया।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में हाई कोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 18 फरवरी को

कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायालय हस्तक्षेप न करता तो मामला दबा दिया जाता

सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी डी.जी.पी. से तलब

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-मोहाली में बढ़ती रंगदारी, फायरिंग की घटनाओं तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में नाम आने के बाद. मोहाली के एस.एस.पी. हरमनदीप सिंह हंस की भूमिका को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर मामलों पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत की सहायता कर रहीं अधिवक्ता तनु बेदी ने बताया कि कई नागरिक लगातार रंगदारी के फोन आने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई प्रभावी नजर नहीं आ रही। इस पर हाई कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि इन शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई पर पेश किया और संगठित अपराध के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है। अदालत ने विशेष रूप से मोहाली के एस.एस.पी. को लेकर सरकार से पूछा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में उनका नाम जांच रिपोर्ट में आने के बावजूद क्या राज्य सरकार उनके कार्य से संतुष्ट है। सरकार की ओर से संतोष जताने पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी अदालत को दी जानी चाहिए। बाद में सरकार ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों को चार्जशीट किया गया था, जिनमें वर्तमान एस.एस.पी. का नाम भी शामिल है। इसी सुनवाई के दौरान मोहाली कोर्ट के एक चौकीदार को पुलिस इंस्पैक्टर द्वारा पीटे जाने के मामले में भी हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया। सरकार ने बताया कि आरोपी इंस्पैक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अदालत में चालान दाखिल किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि अगर न्यायालय हस्तक्षेप न करता तो मामला दबा दिया जाता। हाई कोर्ट ने डी.जी.पी. से मोहाली में पुलिस बल की तैनाती, हाल के वर्षों में हुई फायरिंग की घटनाओं और कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुई हत्याओं के संभावित आपसी संबंधों पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि जिस प्रकार निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित अवधि की पोस्टिंग नीति लागू है, उसी तरह वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

आयोग के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण हो जरूरी-कोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अर्ध-न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले वैधानिक निकायों के सदस्यों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं, प्रक्रिया संबंधी अनुशासन और न्यायिक संयम के बारे में समुचित प्रशिक्षण दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे पदों पर कार्यरत सदस्यों को मीडिया तथा सार्वजनिक मंचों पर भी संयम बरतने की आवश्यकता है। यह टिप्पणी उस समय सामने आई जब अदालत ने एक स्वत: संज्ञान मामले में आयोग द्वारा मोहाली और पटियाला के अस्पतालों के डाक्टरों तथा निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों पर रोक लगा दी। मामला कथित रूप से बकाया बिल के कारण मरीज का शव रोककर रखने से जुड़ा था।

हेलीपेड पर दो मुख्यमंत्री की अचानक मुलाकात ने सियासी हलकों में बढ़ाई हलचल

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)-चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क हेलीपेड पर गुरुवार को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की यहां अचानक मुलाकात हो गई। खास बात यह रही कि एसवाईएल मुद्दे पर हालिया संयुक्त बैठक के बाद यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने भेंट थी। दरअसल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को फरीदाबाद दौरे पर जाना था। वे निर्धारित कार्यक्रम के तहत राजेंद्र पार्क हेलीपेड पहुंच गए। इसी दौरान सूचना मिली कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हेलीकॉप्टर पंजाब दौरे से लौटते हुए लैंड करने वाला है। चूंकि दोनों राज्य एक ही हेलीपेड का उपयोग करते हैं, इसलिए एक हेलीकॉप्टर के लैंडिंग या टेकऑफ के दौरान दूसरा उड़ान नहीं भर सकता। ऐसे में नायब सैनी ने अपने आवास लौटने की बजाय वहीं रुककर इंतजार करना उचित समझा। कुछ ही देर में भगवंत मान का हेलीकॉप्टर उतरा और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। मुलाकात भले ही औपचारिक और संक्षिप्त रही हो, लेकिन एस.वाई.एल. जैसे संवेदनशील मुद्दे की पृष्ठभूमि में इसे राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों मुख्यमंत्री बातचीत के बाद अपने-अपने कार्यक्रमों के लिए निकल गए।

चंडीगढ़ को 'पीएम ई-बस सेवा योजना' के तहत मिली 25 नई अत्याधुनिक इलैक्ट्रिक बसें

चंडीगढ़ (सत्ता संदेश)- चंडीगढ़ को 'पीएम ई-बस सेवा योजना' के तहत 25 नई अत्याधुनिक इलैक्ट्रिक बसें मिली हैं। इन बसों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पैनिक बटन और सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए ऑटोमैटिक रैंप और लो-फ्लोर डिजाइन (400 मिमी) की सुविधा दी गई है, जिससे चढ़ना-उतरना आसान होगा। 15 मीटर लंबी ये फुली एसी बसें एक बार फुल चार्ज होने पर 224 किलोमीटर तक चल सकती हैं। इनमें 36 बैठने और 20 खड़े यात्रियों की क्षमता है। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और स्टॉप के लिए पुश बटन लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कुल 100 ई-बसों को मंजूरी दी है। पहली खेप में 25 बसें पहुंच चुकी हैं, जबकि 25 और फरवरी के अंत तक तथा शेष 50 बसें मार्च-अप्रैल तक आने की उम्मीद है। नवंबर 2025 में 85 पुरानी डीजल बसों को हटाने के बाद पैदा हुई कमी को ये बसें पूरा करेंगी। प्रशासन का लक्ष्य प्रमुख रूटों पर हर 10 मिनट में बस उपलब्ध कराना है, ताकि ट्राइसिटी के यात्रियों को बेहतर और प्रदूषण मुक्त सफर मिल सके।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में संलिप्तता के आरोप को निखिल गुप्ता ने स्वीकारा

न्यूयार्क (सत्ता संदेश)- खालिस्तानी अलगाववादी नेता प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित हत्या की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। 54 वर्षीय गुप्ता ने अमेरिका की एक अदालत में 'मर्डर-फॉर-हायर' (किराए पर हत्या), हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे आरोपों को स्वीकार कर लिया। इससे पहले जून 2024 में उन्होंने संघीय अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। असफल हत्या प्रयास के बाद गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। तब से वे बिना जमानत के हिरासत में हैं और दोष सिद्ध होने पर उन्हें कई दशक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश रची। हालांकि नई दिल्ली ने इन आरोपों से खुद को अलग करते हुए कहा है कि यह कथित साजिश सरकारी नीति के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित किया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है। इस कथित साजिश ने पहले भी भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव पैदा किया था। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया था कि गुप्ता विदेशों में सिख अलगाववादी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे, जिसमें जून 2023 में पश्चिमी कनाडा के एक सिख मंदिर के बाहर नकाबपोश हमलावरों द्वारा की गई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। अमेरिका का दावा है कि गुप्ता ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी विकास यादव के निर्देश पर पन्नू की हत्या के लिए शूटर को हायर किया था। इस मामले में यादव पर भी आरोप तय किए गए हैं, हालांकि वे फिलहाल भारत में ही हैं। मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी और इस हाईप्रोफाइल केस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।